VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365 सारांश

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

विषय सूची

1. बदलती विश्व व्यवस्था की गतिशीलता (DYNAMICS OF CHANGING WORLD ORDER).. 5

1.1. उभरती विश्व व्यवस्था (EMERGING WORLD ORDER) 5

1.2. वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका (INDIA'S ROLE IN GLOBAL DIPLOMACY) 5

1.2.1. विश्व में शांति स्थापक के रूप में भारत की भूमिका (INDIA'S ROLE AS A GLOBAL PEACEMAKER) 5

1.2.2. भारत और ग्लोबल साउथ (INDIA AND THE GLOBAL SOUTH) 6

1.3. मिनीलैटरल का उदय (Rise of Minilaterals) 6

1.4. वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भू-राजनीतिक जोखिम (GEOPOLITICAL RISK TO GLOBAL ECONOMY) 7

1.4.1. चाइना-प्लस-वन रणनीति (CHINA-PLUS-ONE STRATEGY) 7

1.5. अंतरिक्ष कूटनीति (SPACE DIPLOMACY) 7

1.6. परमाणु हथियार शस्त्रागार का बढ़ना (RISE IN NUCLEAR WEAPONS ARSENAL) 8

1.7. भारतीय प्रवासी (INDIAN DIASPORA) 8

2. भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते (REGIONAL, AND GLOBAL GROUPING AND AGREEMENTS INVOLVING INDIA AND/OR AFFECTING INDIA'S INTEREST) 10

2.1. भारत और हिंद-प्रशांत: एक नजर में (India-Indo Pacific at a Glance) 10

2.1.1. हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative: IPOI) 10

2.2. क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग/ क्वाड (QUAD) 11

2.3. ऑकस (AUKUS) 11

2.4. ब्रिक्स का विस्तार (Expansion of BRICS) 12

2.5. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization: SCO) 12

2.6. आसियान (ASEAN) 13

2.7. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन: सार्क (SAARC) 13

2.8. बिम्सटेक (BIMSTEC) 14

2.9. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor) 14

2.10. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20) शिखर सम्मेलन (G20 Summit) 15

2.11. G7 15

2.12. नाटो (NATO) 16

3. भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध (INDIA AND ITS NEIGHBOURHOOD RELATIONS) 17

3.1.भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (India's Neighbourhood First Policy) 17

3.2. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष (India-75 Years of India-China Relations) 17

3.2.1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China-Pakistan Economic Corridor: CPEC) 18

3.3. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) 19

3.3.1. शिमला समझौता (Shimla Agreement) 19

3.4. भारत-श्रीलंका संबंध (India – Sri Lanka Relations) 20

3.5. भारत-अफगानिस्तान संबंधों में बदलाव (Shift in India–Afghanistan Relations) 20

3.6. भारत-बांग्लादेश संबंध (India-Bangladesh Relations) 21

3.7. भारत-नेपाल संबंध (India-Nepal Relations) 21

3.8. भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relations) 22

3.9. भारत-भूटान संबंध (India-Bhutan relations) 22

3.10. हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) 23

4. भारत से जुड़े और/या भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह और समझौते (BILATERAL GROUPING AND AGREEMENTS INVOLVING INDIA AND/OR AFFECTING India)........................24

4.1. भारत-पश्चिम एशिया (India-West Asia) 24

4.1.1. पश्चिम एशिया में भारत की संतुलित विदेश नीति (India's Foreign Policy Balancing in West Asia) 24

4.2. भारत- जापान संबंध (India-Japan Relations) 25

4.3. भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया (India and South East Asia) 26

4.3.1. भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष (10 Years of India's Act East Policy) 26

4.4. भारत-प्रशांत द्वीपीय देश संबंध (India-Pacific Islands Nations Relations) 27

4.5. भारत और मध्य एशियाई गणराज्यों के संबंध 28

(India and Central Asian Republics Relations) 28

4.6. भारत-अफ्रीका संबंध (India-Africa Relationship) 28

4.7. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध (India-U.S.A Relations) 29

4.7.1. संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी उपाय (USA'S PROTECTIONIST MEASURES) 29

4.8. भारत-कनाडा संबंध (India-Canada Relationship) 30

4.9. भारत-यूरोप संबंध (India-Europe) 31

4.9.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-United Kingdom Relations) 31

4.9.1.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम विज़न 2035 तथा व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता {India-UK Vision 2035 and Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)} 31

4.9.2. भारत-यूरोपीय संघ संबंध {India-European Union (EU) Relations} 31

4.9.3. भारत-फ्रांस संबंध (India-France Relations) 32

4.9.4. भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations) 32

4.9.5. भारत-यूरेशिया संबंध (India-Eurasia Relations) 33

4.9.6. भारत-नॉर्डिक संबंध (India-Nordic Relations) 34

4.10. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India-Australia Relations) 35

4.11. भारत और LAC (लैटिन अमेरिका और कैरिबियन) क्षेत्र संबंध {India and LAC (LATIN AMERICA and Caribbean) Region Relations} 35

5. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच तथा उनकी संरचना व अधिदेश (IMPORTANT INTERNATIONAL INSTITUTIONS, AGENCIES, AND FORA, THEIR STRUCTURE, MANDATE)........................36

5.1. अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (International Humanitarian Law: IHL) 36

5.2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council) 36

5.3. भारत और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (India and UN Peacekeeping) 37

5.4. ICC 37

5.5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO) 38

5.6. राष्ट्रमंडल (Commonwealth) 38

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल से आवश्यक जानकारी का संकलन कर मेन्स 365 अंतर्राष्ट्रीय संबंध डॉक्यूमेंट का सारांश तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है VisionIAS का Mains 365 स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।
- यह डॉक्यूमेंट हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, चुनौतियों, समाधान की संभावनाओं, आदि का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह सामग्री विशेष रूप से आपके UPSC मेन्स उत्तरों को तथ्यात्मक, संतुलित और समकालीन दृष्टिकोण से समृद्ध करने के लिए तैयार की गई है।
- यह डॉक्यूमेंट आपको प्रमुख टॉपिक को जल्दी और प्रभावी ढंग से रिवाइज करने में मदद करेगा।
- अपनी तैयारी में सुधार करने और UPSC मेन्स में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग कीजिए।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

2026 | ENGLISH MEDIUM 10 AUGUST | हिन्दी माध्यम 10 अगस्त

1. बदलती विश्व व्यवस्था की गतिशीलता (DYNAMICS OF CHANGING WORLD ORDER)

1.1. उभरती विश्व व्यवस्था (EMERGING WORLD ORDER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में बिम्सटेक की बैठक में भारत ने क्षेत्रीय और एजेंडा-विशेष वैश्विक व्यवस्था की ओर बदलाव पर प्रकाश डाला।

नई विश्व व्यवस्था के उद्भव में योगदान देने वाले कारक

- संयुक्त राष्ट्र जैसी युद्धोत्तर संस्थाएं आधुनिक संकटों के समाधान में सफल सिद्ध नहीं हो रही हैं।
- वैश्विक बहु-संकट (युद्ध, महामारी, जलवायु परिवर्तन) प्राथमिकताओं को नया आकार दे रहे हैं।

भारत के लिए अवसर	चुनौतियां
❖ ग्लोबल साउथ की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में भारत; भारत ने G20 समूह में अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ❖ हरित कूटनीति (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन-ISA) का समर्थन करना। ❖ बहुध्रुवीय मंचों (ब्रिक्स, क्वाड) में संलग्न है।	❖ निष्क्रिय विश्व व्यापार संगठन व्यापार को बाधित करता है। ❖ जलवायु वित्तपोषण पर देशों के मत अलग-अलग हैं। ❖ क्षेत्रवाद आम सहमति बनाने में बाधा डालता है।

निष्कर्ष:

भारत का दृष्टिकोण रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय महत्त्व के माध्यम से मजबूत और बहुध्रुवीय साझेदारी को बढ़ावा देता है।

1.2. वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका (INDIA'S ROLE IN GLOBAL DIPLOMACY)

1.2.1. विश्व में शांति स्थापक के रूप में भारत की भूमिका (INDIA'S ROLE AS A GLOBAL PEACEMAKER)

यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष

- हिंसा को तत्काल समाप्त करने का पक्षधर रहा है तथा मानवीय सहायता प्रदान करने की मांग करता है।
- तनावपूर्ण वैश्विक व्यवस्था में कानून और संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए।
- संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान का समर्थन करता है।

भारत का योगदान	बाधाएं
❖ ग्लोबल साउथ का नेतृत्व (उदाहरण के लिए, अफ्रीकी संघ (AU) को G-20 में शामिल करने का प्रयास)। ❖ श्रीलंका के गृहयुद्ध में मध्यस्थता करना। ❖ विकास में भागीदारी के जरिए शांति स्थापना (उदाहरणार्थ, अफगानिस्तान में सलमा बांध का निर्माण)।	❖ पाकिस्तान/ चीन के साथ सीमा तनाव। ❖ घरेलू चुनौतियां और संसाधनों की कमी। ❖ पश्चिमी देशों के नजदीक रहने का आरोप और सीमित कूटनीतिक संलग्नता।

आगे की राह

- विश्वबंधु (विश्व का मित्र) के रूप में भारत की भूमिका।
- भागीदारी बढ़ाना (जैसे, ब्राजील, नॉर्वे)।
- एक अलग 'शांति स्थापना यूनिट' का गठन करना।
- 5-S दृष्टिकोण (सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि) लागू करना।

निष्कर्ष:

भारत की शांति कूटनीति वास्तव में विश्वसनीय ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता और उभरते हुए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में इसके उदय को दर्शाती है।

1.2.2. भारत और ग्लोबल साउथ (INDIA AND THE GLOBAL SOUTH)

ग्लोबल साउथ क्या है?

- **परिभाषा:** ग्लोबल साउथ शब्दावली सामान्यतः **अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका** के देश के अल्पविकसित **देशों** को व्यक्त करती है। ये देश मुख्य रूप से **दक्षिणी गोलार्ध** में अवस्थित हैं।
- **ब्रांट रिपोर्ट:** उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच उनकी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद, आदि के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था।

ग्लोबल साउथ द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां:

- **कम प्रतिनिधित्व:** अफ्रीका/ लैटिन अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर रखा गया है।
- **ऋण संकट:** विकासशील देशों का ऋण विकसित देशों की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ रहा है (अंकटाड)।
- **जलवायु संकट का सामना:** समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण प्रशांत द्वीप समूह के देश सबसे अधिक संकट का सामना कर रहे हैं {विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)}।
- **वैचारिक विभाजन:** लोकतंत्र/मानवाधिकार मानदंडों पर ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ मतभेद।

भारत के लिए ग्लोबल साउथ का महत्त्व	भारत की स्थिति
• विश्व का नेतृत्व करने की भारत की आकांक्षा का **समर्थन करता है।** • **"बहु-दिशात्मक सहयोग" के माध्यम से** चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना। • **संसाधन** और निर्यात बाजार प्रदान करता है।	• **परियोजनाएँ और सहायता** (जैसे, वैक्सीन मैत्री पहल, ऑपरेशन ब्रह्मा)। • **क्षमता निर्माण** (भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल)। • **जलवायु एजेंडे का नेतृत्व करना {**अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)}।

निष्कर्ष:

भारत समावेशी, तकनीक-संचालित, जन-केंद्रित नेतृत्व को बढ़ावा देता है - जो वित्तीय सहायता की बजाय G20 और ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के जरिए न्यायसंगत सहयोग पर आधारित है।

1.3. मिनीलैटरल का उदय (Rise of Minilaterals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी की आक्रामकता ने **'स्क्वाड/ SQUAD'** के उद्भव को प्रेरित किया है। यह **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया** और **फिलीपींस** के बीच एक मिनिलैटरल समूह है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह क्वाड (QUAD); ऑकस (AUKUS), I2U2 जैसे अनौपचारिक और लक्षित समूहों के प्रति बढ़ती प्राथमिकता को रेखांकित करता है।

मिनीलैटरल समूह क्या होते हैं?

इनमें शामिल देशों की संख्या **कम (आमतौर पर 3 या 4)** होती है, जो विशिष्ट खतरों या एजेंडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मिनीलैटरल समूहों के उदय के पीछे उत्तरदायी कारण	
बहुपक्षीय संस्थाओं की विफलता	**मिनीलैटरलिज्म के लाभ**
• **ये संस्थाएं उभरते खतरों** से निपटने में विफल रही हैं। **(जैसे, चीन की आक्रामकता के मामले में आसियान की निष्क्रियता)** • महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता आम सहमति को बाधित कर रही है (**जैसे, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद)।** • **चीन के अधिक आक्रामक** होने के कारण **क्वाड, AUKUS** जैसे मिनीलैटरल समूहों का उदय हुआ है।	• बहुपक्षवाद के कठोर ढांचे की तुलना में अधिक लचीला और सहमति-उन्मुख। • लक्षित सहयोग को सक्षम बनाता है **(उदाहरण के लिए, भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति श्रृंखला पहल)।** • विवैश्वीकरण और व्यापार संघर्षों के दौरान प्रभावी **(उदाहरण के लिए, अमेरिका-चीन तनाव को दरकिनार करना)।**
भारत को मिलने वाले लाभ	**चुनौतियां**
• रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है **(जैसे, क्वाड)।** • ग्लोबल साउथ के मुद्दों {**उदाहरण के लिए, भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA)} को बढ़ावा देता है।** • त्रिपक्षीय गठबंधन **(उदाहरण के लिए, INSTC पर भारत-ईरान-आर्मेनिया त्रिपक्षीय गुट)।**	• इसमें ग्लोबल साउथ **का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है जैसे कि भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह में है।** • कम संसाधन और समझौतों को लागू करने की क्षमता की कमी। • गुटीय राजनीति को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:
भारत को **"सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय"** के सिद्धांत से प्रेरित होकर बहुपक्षीय सुधारों और मिनीलैटरलिज्म की अवधारणा के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

1.4. वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भू-राजनीतिक जोखिम (GEOPOLITICAL RISK TO GLOBAL ECONOMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IMF की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में व्यापक वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले उच्च भू-राजनीतिक जोखिमों की ओर संकेत किया गया है।

भू-राजनीतिक जोखिम	प्रभाव
❖ व्यापार को शस्त्र के रूप में उपयोग (उदाहरण के लिए, रूसी तेल खरीदारों पर अमेरिका द्वारा दोहरे टैरिफ लगाने की चेतावनी)। ❖ आपूर्ति श्रृंखला खतरे (संघर्ष, साइबर अटैक की वजहों से)। ❖ वैश्विक कंपनियों पर कर लगाने को लेकर मतभेद (वैश्विक न्यूनतम कर बनाम एकतरफा कदम)। ❖ कार्यबल में बढ़ता तनाव (बढ़ती उम्र, एआई व्यवधान, अलग-अलग संस्कृतियां)।	❖ वैश्विक कनेक्टिविटी की वजह से वित्तीय संकट के प्रभाव में आना। ❖ वृहद आर्थिक व्यवधान (पूंजी वापस देश से बाहर जाना, मुद्रास्फीति)। ❖ निवेशकों का विश्वास कम होना (जैसे, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध)। ❖ वैश्विक संस्थाओं का कमजोर होना (डब्ल्यूटीओ की शक्ति कम होना)।

निष्कर्ष
GEF से जुड़े जोखिम से निपटने के लिए बफर का निर्माण करना चाहिए, रणनीतिक तैयारी करनी चाहिए, और छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे व्यापारिक समूहों वाली वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक निर्भरता से जुड़े खतरों को कम करना चाहिए।

1.4.1. चाइना-प्लस-वन रणनीति (CHINA-PLUS-ONE STRATEGY)

चाइना-प्लस-वन रणनीति के तहत कंपनियां केवल चीन से आपूर्ति पर निर्भर रहने की बजाय अन्य देशों में विनिर्माण में निवेश करती हैं ताकि चीन से व्यवधान की स्थिति में अन्य देशों से आपूर्ति जारी रखी जा सके।

चाइना-प्लस-वन रणनीति के लिए उत्तरदायी कारक	चाइना-प्लस-वन रणनीति का लाभ उठाने में भारत पीछे क्यों?
❖ अमेरिका-चीन व्यापार तनाव ❖ चीन में श्रम और कानूनों के पालन की लागत का बढ़ना। ❖ चीन की नीतियों पर देशों का विश्वास कम हो जाना:	❖ वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क के साथ कम एकीकरण। ❖ संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ ❖ भारत ने प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में शामिल होने से परहेज किया (जैसे- RCEP में भारत शामिल नहीं हुआ)

निष्कर्ष
अमेरिका से लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश बाहर जाता है, यदि भारत को इसका केवल 5% भी मिल जाए, तो इससे प्रतिवर्ष भारत को 200 बिलियन डॉलर की विदेशी निवेश प्राप्त हो सकता है, जो वर्तमान में भारत की GDP के 2.5% के विदेशी निवेश को दोगुना कर देगा।

1.5. अंतरिक्ष कूटनीति (SPACE DIPLOMACY)

अंतरिक्ष कूटनीति क्या है?

अंतरिक्ष कूटनीति, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने और विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

अंतरिक्ष कूटनीति की दिशा में भारत के प्रयास

- **वैश्विक सहयोग:** निसार (NISAR) मिशन, **आर्टेमिस एकॉर्ड** में भारत की भागीदारी।
- **उपग्रह प्रक्षेपण:** 163 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण (2019-24), नेपाल को उपग्रह विकास में सहायता प्रदान की।

महत्त्व	चुनौतियां
❖ **वैश्विक चुनौतियों का समाधान करती है:** (उदाहरण के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए उपग्रह डेटा साझा करना।) ❖ **संघर्ष को रोकती है और शस्त्र नियंत्रण सुनिश्चित करती है:** (उदाहरण -बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष में 'सामूहिक विनाश के हथियारों' पर प्रतिबंध लगाती है।) ❖ **अंतरिक्ष कानून और प्रशासन सुनिश्चित करती है:** (उदाहरण के- संयुक्त राष्ट्र COPUOS अंतरिक्ष कानूनों और नीतियों पर चर्चा करता है।) ❖ **अंतरिक्ष कचरे से जुड़े जोखिमों को कम करती है:**	❖ **नेतृत्व और सहयोग में संतुलन:** (उदाहरण-सार्क उपग्रह भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाता है, लेकिन पड़ोसियों की तकनीकी निर्भरता को लेकर चिंताएँ भी बढ़ाती है।) ❖ **तकनीकी कमियाँ:** कुछ अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के मामले में भारत **अमेरिका और चीन** से पीछे है। ❖ **दोहरे उपयोग वाली तकनीक को लेकर चिंताएँ (**भारत का **ASAT परीक्षण** और मिसाइल कार्यक्रम कई देशों की नजर में) ❖ निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर समस्या।

निष्कर्ष

भारत को समावेशी, शांतिपूर्ण अंतरिक्ष कूटनीति का नेतृत्व करना चाहिए और ग्लोबल साउथ की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ निष्पक्ष वैश्विक नियम सुनिश्चित करने चाहिए।

1.6. परमाणु हथियार शस्त्रागार का बढ़ना (RISE IN NUCLEAR WEAPONS ARSENAL)

SIPRI ईयर बुक रिपोर्ट, 2024 के मुख्य बिंदु

- **परमाणु हथियारों (वॉरहेड) में वृद्धि:** भारत के पास 2023 में 164 परमाणु हथियार थे जो से बढ़कर 2024 में 172 हो गए। भारत के पास पाकिस्तान से दो परमाणु हथियार अधिक हैं।
- **विश्व में परमाणु हथियारों की स्थिति:** विश्व में कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग **2,100 हाई अलर्ट पर** हैं (लॉन्च के लिए तैयार)।

राष्ट्र परमाणु हथियार क्यों रखना चाहते हैं?

- प्रतिद्वंद्वियों से सुरक्षा सुनिश्चित करना (जैसे, चीन-पाकिस्तान एक्सिस) का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार हासिल करते हैं। परमाणु हथियार के बहाने आतंकवाद द्वारा ब्लैकमेलिंग का जवाब।
- **"परमाणु लॉबी":** सेना, वैज्ञानिक और राजनेता संस्थाओं पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों को बढ़ाने पर ज़ोर देते हैं।
- **महाशक्ति का प्रतीक:** परमाणु हथियार क्षमता भू-राजनीतिक शक्ति और प्रभाव प्रदान करती है (जैसे, परमाणु हथियार वाले पांच देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है)।

परमाणु हथियार से जुड़े खतरे को कम करने के प्रस्ताव

- **नो-फर्स्ट-यूज़ के लिए प्रतिबद्धता:** इस सिद्धांत के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और NATO देशों की प्रतिबद्ध होना पड़ेगा।
- सभी सामरिक (टैक्टिकल) परमाणु हथियारों को केंद्रीय भंडारण में रखने और इनका **समय-समय पर थर्ड पार्टी को सत्यापित करने की अनुमति** देनी चाहिए।
- **परमाणु हथियारों की संख्या धीरे-धीरे कम** करनी चाहिए। **द्विपक्षीय परमाणु समझौता** करना चाहिए। इनमें परमाणु सामग्रियों का हथियार बनाने में उपयोग होने पर इन सामग्रियों की आपूर्ति रोकने से संबंधित प्रावधान होने चाहिए।

निष्कर्ष

जैसा कि P5 संयुक्त वक्तव्य में दोहराया गया है, परमाणु हथियारों का उद्देश्य केवल प्रतिरोधकता (डिटरेंस) होना चाहिए, और परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं।

1.7. भारतीय प्रवासी (INDIAN DIASPORA)

इंडियन डायस्पोरा के बारे में

- भारत सरकार ने 'प्रवासी' समुदाय की कोई सटीक परिभाषा नहीं दी है, लेकिन आमतौर पर इनमें **अप्रवासी भारतीय (NRI) और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI)** शामिल होते हैं। (2015 में **PIO और OCI कार्डधारकों को OCI नामक एकल श्रेणी में विलय** कर दिया गया।)
- भारत की प्रवासी नीति को **"4C" (केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट & कंट्रीब्यूट)** के रूप में परिभाषित किया जाता है।

भारतीय प्रवासियों का महत्व	
भारत के लिए महत्त्व	**गंतव्य देशों के लिए महत्त्व**
❖ **सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव:** त्योहारों, भाषाई विद्यालयों के माध्यम से **भारतीय परंपराओं का संरक्षण** करते हैं। ❖ **आर्थिक प्रभाव:** रेमिटेंस के रूप में भारत को **2023 में 125 बिलियन डॉलर** प्राप्त हुए, जो **GDP का लगभग 3.4%** है। **सुंदर पिचाई (गूगल)**। ❖ **राजनीतिक प्रभाव:** ऋषि सुनक, कमला देवी हैरिस जैसे राजनेता भारत के प्रभाव को बढ़ाते हैं। ❖ **कूटनीति संबंध:** प्रवासी भारतीय अपने प्रवास देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं (भारत-अमेरिका परमाणु समझौता में भूमिका)।	❖ **सांस्कृतिक विविधता:** भारतीय परंपराओं, भाषाओं आदि के द्वारा स्थानीय संस्कृति को विविधता प्रदान करते हैं। ❖ **श्रम आपूर्ति:** खाड़ी देशों में कार्यबल की कमी को पूरा करता है (निर्माण, स्वास्थ्य-देखभाल सेवा में)। ❖ **उद्यमिता:** प्रवास वाले देश में इनोवेशन और रोजगार सृजन में योगदान देते हैं (**कुवैत में लगभग 1 मिलियन** भारतीय समुदाय)।

प्रवासी सहभागिता को बढ़ाने के लिए आगे की राह

- **कानूनी और नीतिगत सुधार:** प्रवासन विधेयक, 2023 को अंतिम रूप देना, प्रवासी पंजीकरण प्रणाली को बेहतर बनाना।
- **ज्ञान एवं कौशल का उपयोग:** कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ करना और प्रवासी पेशेवरों को भारतीय कंपनियों से जोड़ना।
- **सुरक्षा एवं संरक्षा:** लाभ हस्तांतरण की सुविधा सुनिश्चित करना, कानूनी सहायता और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए परस्पर कानूनी सहायता संधियों (MLATs) को मजबूत करना।

निष्कर्ष

भारतीय प्रवासी दुनिया और भारत के बीच "विरासत से जुड़े जीवंत सेतु (Living Root Bridges)" की भूमिका निभाते हैं। इस रूप में वे सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को सशक्त करते हैं।

2. भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते (REGIONAL, AND GLOBAL GROUPING AND AGREEMENTS INVOLVING INDIA AND/OR AFFECTING INDIA'S INTEREST)

2.1. भारत और हिंद-प्रशांत: एक नजर में (India-Indo Pacific at a Glance)

हिंद-प्रशांत (IP) के बारे में

- **वैश्विक व्यापार का 50%** और 40% तेल व्यापार हिंद-प्रशांत क्षेत्र से गुजरता है। भारत का 90 प्रतिशत व्यापार इस क्षेत्र से होता है।
- अमेरिका-चीन महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बन गया है।

हिंद-प्रशांत के लिए भारत के विज़न	हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नीति
• मुक्त, खुला व समावेशी क्षेत्र का समर्थन; हिंद प्रशांत के केंद्र में आसियान। • क्षेत्र के लिए एक साझा **नियम-आधारित व्यवस्था** का समर्थन और बल प्रयोग की बजाय संवाद को बढ़ावा देता है।	• सुरक्षा प्रदाता: अपनी सामुद्रिक भूमिकाओं को मजबूत कर रहा है (संकट में प्रथम मददगार के रूप में सामने आना)। • **नौसैनिक रणनीति:** सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र **(IMAC)** के माध्यम से **समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA)** में भूमिका।
हिंद-प्रशांत में भारत के हित	**चुनौतियां**
• अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना। • **चीन के बढ़ते प्रभाव** को प्रतिसंतुलित करना; **निवल सुरक्षा प्रदाता** के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखना।	• सीमित **नौसैनिक क्षमता** और विदेशों में भारतीय सैन्य अड्डों की कमी। • विभिन्न पहलों के विकास की धीमी गति, **हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर निश्चित सहमति का अभाव।**

निष्कर्ष

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वैश्विक राजनीति को अहम भूमिका है, और भारत को इस क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले देश के रूप में देखा जाता है।

2.1.1. हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative: IPOI)

IPOI के बारे में

- यह एक **गैर-संधि आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है, जिसे** भारत ने **2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत तथा नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था** के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए लॉन्च किया।
- **उद्देश्य:** व्यावहारिक सहयोग के जरिए **नई साझेदारी बनाना, भारत की सागर/SAGAR** पहल की अवधारणा पर आधारित।

महत्त्व	चुनौतियां
• **समग्र दृष्टिकोण:** सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण को एकीकृत करती है ((जैसे, आसियान सिनर्जी))। • **चीन के आक्रामक व्यवहार से निपटना:** नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा (उदाहरण- भारत और वियतनाम समझौता) • **समुद्री गवर्नेंस:** यह सहयोग आधारित सुरक्षा तथा क्रिटिकल मिनरल्स (लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व) के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देती है। • **लचीला फ्रेमवर्क:** इसके समझौते बाध्यकारी नहीं हैं इसलिए नए खतरों के अनुरूप अनुकूल प्रतिक्रिया निर्धारित करने में मदद करती है।	• **संस्थागत क्षमता एवं कार्रवाई की कमी:** इस पहल के प्रत्येक स्तंभ के लिए सुपरिभाषित एजेंडा का अभाव है। (जैसे; समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ). • **भू-राजनीतिक तनाव:** चीन **IPOI** को उसका **विरोध करने वाली रणनीतियों का हिस्सा** मानता है। • **संसाधन की कमी:** वित्तीय सहायता सीमित होना और विभिन्न देशों की अलग-अलग नीतियाँ। • **प्रतिनिधित्व की कमी:** पूर्वी अफ्रीका, खाड़ी देशों और लघु द्वीपीय देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं।

निष्कर्ष

IPOI भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** का हिस्सा है, जो रणनीतिक साझेदारियों (जापान, ऑस्ट्रेलिया) को साथ लेकर अपने संबंधों को संतुलित करने पर आधारित है। यह **नौवहन की स्वतंत्रता** और सहयोग पर आधारित क्षेत्रीय फ्रेमवर्क का समर्थन करता है।

2.2. क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग/ क्वाड (QUAD)

भारत के लिए क्वाड का महत्त्व	चुनौतियां
❖ हिंद-प्रशांत में **चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित** करना ❖ **समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना** (मालाबार अभ्यास, UNCLOS का अनुपालन) ❖ **आत्मनिर्भर भारत का समर्थन** ❖ **एक्ट ईस्ट नीति** को बढ़ावा देना	❖ **पूरी तरह से संस्थागत नहीं** (ज्यादातर काम-काज नियमित बैठकों के माध्यम से, दीर्घकालिक समेकन पर खतरा) ❖ अलग-अलग देशों के अलग-अलग राष्ट्रीय हित ❖ चीन ने इस पर 'एशियन नाटो' होने का आरोप लगाया है ❖ **आसियान और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन** जैसे समूहों से अलग परिभाषित करना कठिन
क्वाड से जुड़ी भारत की चिंताएं	**आगे की राह**
❖ **सैन्य गठबंधन के प्रति अनिच्छा** ❖ क्वाड को चीन-विरोधी समूह बनने से रोकना ❖ नए समूह (**SQUAD जिसमें फिलीपींस शामिल हैं**) का गठन क्वाड को कम महत्वपूर्ण बना सकते हैं। ❖ भारत **शंघाई सहयोग संगठन (SCO), रूस और ईरान जैसे देशों** के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है।	❖ एक औपचारिक संरचना देना या आपसी समन्वय के लिए स्थायी सचिवालय की स्थापना करना ❖ आसियान/अन्य (वियतनाम, इंडोनेशिया) का समर्थन करना चाहिए ❖ तनाव कम करने के लिए **सुरक्षा से परे क्षेत्रों** (जैसे: स्वास्थ्य-देखभाल, अवसंरचना विकास) पर सहयोग बढ़ाना चाहिए

2.3. ऑकस (AUKUS)

AUKUS के बारे में

- **सदस्य:** ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका (2021 के त्रिपक्षीय रक्षा समझौता के आधार पर गठन)
- **पिलर I –** ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियां बनाने में मदद करना।
- **पिलर II –** साइबर सिक्योरिटी, AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों **के क्षेत्र में सहयोग**।

हिंद-प्रशांत के लिए सामरिक निहितार्थ:

- **सामरिक:** स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के विज़न को साकार करना।
- **अमेरिका की प्रतिबद्धता:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अमेरिका की मजबूत प्रतिबद्धता।
- **यूनाइटेड किंगडम की भूमिका:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में इसकी आकांक्षा को पूरा करने में योगदान देगा।

AUKUS बनाम क्वाड	
AUKUS	**क्वाड**
❖ रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता (सबमरीन, AI) ❖ केवल तीन सदस्य (भारत/जापान शामिल नहीं)	❖ व्यापक सहयोग (स्वास्थ्य, जलवायु, सुरक्षा) ❖ 4 सदस्य (भारत/जापान सहित)

भारत की स्थिति	
अवसर	**चिंताएं**
❖ **क्वाड का पूरक बनकर** साझा खतरे के रूप में चीन से निपटने में सक्षम ❖ **फ्रांस/यूरोप** के साथ सहयोग मजबूत करने के अवसर {भारत-फ्रांस-UAE **(2023)}**	❖ पनडुब्बियों की बढ़ती उपस्थिति से हिंद महासागर में भारत के **प्रभाव में कमी** आ सकती है। ❖ **अमेरिका की इंडो-पैसिफिक की संकीर्ण परिभाषा में** अफ्रीका और मध्य पूर्व शामिल नहीं।

निष्कर्ष

AUKUS ने भारत के सामने कुछ दुविधाओं को रेखांकित किया है, जैसे: क्या रक्षा साझेदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता बढ़ाई जाए या क्षेत्र में नेतृत्व के अवसर के साथ समझौता किया जाए।

2.4. ब्रिक्स का विस्तार (Expansion of BRICS)

विस्तार का महत्व	चुनौतियां
❖ **बहुध्रुवीय विश्व को आकार देने में महत्त्व:** मध्यवर्ती शक्तियां (मिड पावर) तेजी से केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। ❖ **ब्रिक्स समूह के फुटप्रिंट का विस्तार:** अब इसमें मध्य पूर्व (सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात), अफ्रीका (मिस्र, इथियोपिया), लैटिन अमेरिका (अर्जेंटीना) शामिल हैं। ❖ **वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभाव:** ब्रिक्स देशों ने क्रय शक्ति समता के मामले में G7 देशों को पीछे छोड़ दिया, नए सदस्यों से वैश्विक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।	❖ **विकास के विविध स्तर:** ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए देशों के आर्थिक विकास का स्तर काफी अलग-अलग है। ❖ **चीन का प्रभाव:** ब्रिक्स की विस्तार नीति को चीन की रणनीति के रूप में देखा जाता है। ❖ **अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं:** सदस्य देश लोकतांत्रिक एवं सत्तावादी शासनों का मिश्रण है। ❖ **वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के प्रति दृष्टिकोण:** UNSC जैसी संस्थाओं में सुधारों के प्रति ठोस दृष्टिकोण नहीं।

आगे की राह

- **संस्थागत व्यवस्था:** एक स्थायी सचिवालय होना जरूरी है।
- **संरक्षणवाद के खिलाफ सामूहिक रुख:** भविष्य व्यापार संबंधी संरक्षणवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों के सामूहिक रुख पर निर्भर करेगा।
- **नवाचार:** ब्रिक्स वीज़ा, अंतरिक्ष संघ, पारंपरिक चिकित्सा डेटाबेस
- **ग्लोबल साउथ का नेतृत्व:** विकास आधारित एजेंडा को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

आंतरिक विरोधाभासों के बावजूद, विस्तारित ब्रिक्स बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देता है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैकल्पिक वित्तीय/ राजनीतिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

2.5. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization: SCO)

SCO में भारत के रणनीतिक अवसर	भारत की चिंताएं
❖ **मध्य एशिया से संपर्क का माध्यम:** भारत की **"कनेक्ट सेंट्रल एशिया" नीति** को सशक्त करता है। ❖ **संसाधन की आपूर्ति**: भारत कज़ाखस्तान के यूरेनियम संसाधनों को प्राप्त कर सकता है, INSTC जैसी परियोजनाओं को समर्थन मिल सकता है। ❖ **नियंत्रित सहयोग: SCO-क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS)** के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग में भागीदारी, लेकिन **चीन की BRI का समर्थन करने से बचना**।	❖ SCO में **चीन का वर्चस्व:** चीन अपनी **(BRI** का जोर-शोर से प्रचार करता है। ❖ **सदस्यता विस्तार से जुड़ी समस्याएं**: बेलारूस जैसे नए सदस्य SCO के मुख्य फोकस को कमजोर करते हैं। ❖ **कम प्रभावी होना:** निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, (NAM जैसे **चर्चा केंद्र की तरह** कार्य करता है।
SCO की वैश्विक भूमिका	**भारत की संतुलनकारी रणनीति**
❖ **भू-राजनीतिक विस्तार:** यह फोरम यूरेशिया के 80% क्षेत्र और विश्व की 42% जनसंख्या को कवर करता है। ❖ **आर्थिक प्रभाव: वैश्विक GDP में लगभग 25% का योगदान** देते हैं। ❖ **अफगानिस्तान की सुरक्षा:** नाटो सेना की वापसी के बाद की वहां की सुरक्षा स्थिति पर निगरानी।	❖ **चुनिंदा भागीदारी: SCO-RATS** के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग में भारत की भागीदारी। ❖ **रूस के साथ साझेदारी**: गैर-विवादित पहलों में सहयोग। ❖ **रेड लाइन्स:** पश्चिम विरोधी या चीन-केंद्रित प्रस्तावों का विरोध करता है।

निष्कर्ष

भारत **SCO** को मध्य एशिया देशों के साथ संबंधों के लिए एक व्यावहारिक फोरम मानता है, लेकिन इसे चीन के नेतृत्व वाले पश्चिम-विरोधी गुट में बदलने का विरोध करता है।

2.6. आसियान (ASEAN)

भारत के लिए आसियान का रणनीतिक महत्व	क्षेत्र में आसियान का महत्त्व
❖ आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है (2023-24 में 122.67 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार ❖ **हिंद-प्रशांत रणनीति**: आसियान सेंट्रलिटी की भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और मलक्का स्ट्रेट से व्यापार की सुरक्षा ❖ **कनेक्टिविटी:** जैसे- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत को जोड़ेगी, आदि। ❖ **सॉफ्ट पॉवर**: पर्यटन और शिक्षा के मामले में आदान-प्रदान।	❖ महाशक्तियों (अमेरिका और चीन) की प्रतिद्वंद्विता के बीच संतुलन की भूमिका ❖ **नियम-आधारित विश्व-व्यवस्था का समर्थक:** आसियान कनेक्टिविटी पर मास्टर प्लान (MPAC) 2025
चुनौतियां	**आगे की राह**
❖ **भारत का व्यापार घाटा**: 2022-23 में बढ़कर 43.57 बिलियन डॉलर हो गया, RCEP से बाहर निकलने से प्रभाव पड़ा है। ❖ **बढ़ता चीनी प्रभाव:** उदाहरण के लिए- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)	❖ **आर्थिक संबंधों को अपग्रेड करना:** आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में संशोधन, व्यापार अवरोधों को कम करना चाहिए। ❖ **समुद्री सुरक्षा:** चीन के प्रतिसंतुलन के लिए भारत को 'हिंद-प्रशांत समुद्री साझेदारी' शुरू करनी चाहिए। ❖ **प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** (जैसे, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग) को पूरा किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की एशियाई सदी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा होने में आसियान की अहम भूमिका है, जो आर्थिक हितों को चीन के विरुद्ध रणनीतिक प्रतिसंतुलन के साथ जोड़ता है।

2.7. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन: सार्क (SAARC)

सार्क की विफलताओं के कारण	पुनर्जीवन देने की आवश्यकता
❖ पिछला सार्क सम्मेलन: 2014 में नेपाल द्वारा आयोजित। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद 2016 का शिखर सम्मेलन स्थगित। ❖ पाकिस्तान की अड़चनें: CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता की अवहेलना करता है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। ❖ संरचनात्मक समस्याएं: विवादों को सुलझाने की कोई व्यवस्था नहीं, सर्वसम्मति से निर्णय लेने की अनिवार्यता निर्णय प्रक्रिया को कठिन बना देती है। ❖ विश्वास की कमी: सदस्य देश भारत के वर्चस्व को लेकर चिंतित।	❖ साझा नीतिगत आवश्यकताएँ: जलवायु परिवर्तन (द. एशिया जलवायु परिवर्तन के खतरों का अधिक सामना कर सकता है), गरीबी। ❖ व्यापार की असीम संभावनाएं: सदस्य देशों के कुल व्यापार में अंतरा-क्षेत्रीय व्यापार केवल 5% है, जबकि आसियान में यह 25% तक है। ❖ विगत सफलताएं: SAFTA, SAARC विकास कोष; सार्क क्षेत्रीय केंद्र।

भारत की दोहरी रणनीति
❖ सार्क के लिए पहलें: दक्षिण एशियाई उपग्रह, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना। ❖ विकल्प: BIMSTEC और 'एक्ट ईस्ट नीति' पर समान रूप से ध्यान ।

आगे की राह

- **मुद्दों पर आधारित सहयोग:** स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु, आपदा राहत पर ध्यान केंद्रित करना।
- **उप-क्षेत्रवाद:** BBIN (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) पहलों को बढ़ावा देना।
- **पाकिस्तान को अलग-थलग करना:** पाकिस्तान रहित सार्क परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।

निष्कर्ष

सार्क दक्षिण एशिया के सामूहिक अस्तित्व के लिए अहम बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के नेतृत्व वाले गतिरोधों को दरकिनार करने के लिए इसमें संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है।

2.8. बिम्सटेक (BIMSTEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

थाईलैंड की अध्यक्षता में **बैंकॉक में छठा बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन** संपन्न हुआ।

बिम्सटेक	भारत के रणनीतिक लाभ
❖ सदस्य: 7 राष्ट्र (भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान) ❖ भारत की भूमिका: सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है, एक्ट ईस्ट/ पड़ोसी पहले नीतियों के अनुरूप है। ❖ सामरिक महत्व: दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है, पाकिस्तान शामिल नहीं है।	❖ सार्क का विकल्प: पाकिस्तान द्वारा जारी गतिरोध के बावजूद सार्क के कार्यात्मक ❖ समुद्री सुरक्षा: बंगाल की खाड़ी के लिए SAGAR (सागर) विजन के अनुरूप। ❖ व्यापार क्षमता: कार्यान्वियन नहीं हुए FTA (मुक्त व्यापार समझौता) के माध्यम से आपसी व्यापार को 6-7% तक बढ़ाया जा सकता है।

चिंताएं

- **संगठन की धीमी प्रगति:** पिछले 27 वर्षों में वर्तमान शिखर सम्मेलन सहित केवल 6 शिखर सम्मेलन ही आयोजित, भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता लागू होने में काफी देरी।
- **चीन की BRI परियोजनाओं का प्रभाव:** भारत और भूटान को छोड़कर सभी सदस्य देश परियोजनाओं का हिस्सा हैं।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थी संकट, भारत-नेपाल सीमा मुद्दा आदि।

आगे की राह

- **तेज़ कनेक्टिविटी:** IMT (भारत-म्यांमार-थाईलैंड) त्रिपक्षीय राजमार्ग को पूरा करना चाहिए।
- **FTA को पुनर्जीवित करना:** अवरुद्ध बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते को लागू करना चाहिए।
- **संकटों से निपटना:** रोहिंग्या, नेपाल-भारत सीमा मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

निष्कर्ष

बिम्सटेक संगठन सार्क की सीमाओं से परे जाते हुए भारत के हिंद-प्रशांत नेतृत्व को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

2.9. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor)

भारत के लिए महत्त्व	मुख्य चुनौतियां
❖ **व्यापार को बढ़ावा:** व्यापारिक जहाजों को यूरोप तक पहुँचने में **स्वेज नहर समुद्री मार्ग** की तुलना में **40% कम समय, व्यापार लागत में 30% तक की कमी**। ❖ **भू-राजनीतिक लाभ: चीन की BRI का विकल्प** प्रस्तुत करता है। ❖ **वैश्विक लक्ष्य: विस्तारित कनेक्टिविटी के माध्यम से यूरोपीय संघ (EU)** और **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) को जोड़कर** भारत के वैश्विक शक्ति बनने की महत्वकांक्षा को पूरा कर सकता है।	❖ **वित्तपोषण की कमी:** स्पष्ट वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं की कमी है। ❖ **क्षेत्रीय अस्थिरता**: इजरायल-हमास युद्ध, हूती विद्रोही, ❖ **लॉजिस्टिक्स बाधाएं:** उच्च लागत, अल्पविकसित विनिर्माण केंद्र। ❖ **महत्वपूर्ण देश शामिल नहीं:** ईरान, इराक जैसे देश शामिल नहीं हैं।

आगे की राह

- **पश्चिम एशिया में स्थिरता सुनिश्चित करना:** निवेश बढ़ाने के लिए संघर्षों का समाधान करना चाहिए।
- **वित्तपोषण सुनिश्चित करना:** वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (PGII) में देशों की प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करना चाहिए।
- **सदस्यता का विस्तार करना:** क्षेत्र के अन्य देशों को इससे जोड़ना चाहिए।

निष्कर्ष

IMEC भारत को यूरोप के बाजार तक तेज गति से पहुँच बढ़ाने के साथ चीन की BRI का एक विकल्प प्रदान करता है, लेकिन इसे समझौता ज्ञापनों (MoUs) से आगे बढ़कर क्रियान्वयन के लिए संघर्ष समाधान और वित्तपोषण सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

2.10. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20) शिखर सम्मेलन (G20 Summit)

G-20 के बारे में	रियो शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु
❖ **स्थापना: एशियाई वित्तीय संकट** के बाद **1999** में। ❖ **सदस्य:** G7+अफ्रीकी संघ, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ, एवं अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। (विश्व की GDP का 85%) ❖ **2024 मेजबानी:** ब्राजील (आयोजित करने वाला **ग्लोबल साउथ का तीसरा देश**। अन्य दो देश हैं- **इंडोनेशिया और भारत)।**	❖ **ऐतिहासिक कदम: अफ्रीकी संघ (AU) ने पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।** ❖ **ग्लोबल साउथ पर बल:** ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका ट्रोइका G-20- IBSA और ब्रिक्स देश हैं। ❖ **भविष्य की मेजबानी:** अगला G-20 **सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका** (2025) करेगा। इस तरह ग्लोबल साउथ द्वारा नेतृत्व का चक्र पूरा होगा।
भारत के लिए रणनीतिक महत्व	**चुनौतियां**
❖ **कूटनीति प्रभाव:** दिल्ली में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन ने "ग्लोबल साउथ" के नेतृत्व के रूप में भारत को प्रस्तुत किया। ❖ **नीतिगत प्रभाव:** अफ्रीकी संघ को शामिल किया, DPI और हरित विकास का समर्थन किया। ❖ **आर्थिक महत्त्व:** G20 देश विश्व की लगभग 85% GDP में योगदान देते हैं, IMEC को बढ़ावा देने में सहायक। ❖ **सॉफ्ट पावर:** G20 की बैठकों के आयोजनों का उपयोग पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया।	❖ **खंडित विश्व:** रूसी राष्ट्रपति व सऊदी क्राउन प्रिंस की अनुपस्थिति, जलवायु कार्य-योजना का अर्जेंटीना द्वारा विरोध। ❖ **संरचनात्मक कमियां**: G20 के **निर्णय बाध्यकारी नहीं होते**, BRICS और SCO जैसे मंचों से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ❖ **अनसुलझे मुद्दे:** G7 और G20 की भूमिकाओं में स्पष्टता की कमी, संपदा कर का विरोध, **COP29 बैठक** होने से पहले जलवायु कार्रवाई की धीमी प्रगति।

निष्कर्ष:

संगठन में कई कमियों के बावजूद, G20 भारत के लिए बहुपक्षवाद में सुधार करने, 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को बुलंद करने और व्यापार-जलवायु-प्रौद्योगिकी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

2.11. G7

G-7 के बारे में	भू-राजनीतिक प्रासंगिकता
❖ **सदस्य:** कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका (विकसित औद्योगिक देश)। ❖ **भूमिका:** प्रतिबंध लगाने में समन्वय दिखाया (रूस), ग्लोबल गवर्नेंस (**OECD/FATF**), नियम आधारित व्यवस्था।	❖ **सुरक्षा सुनिश्चित करने के नेतृत्व:** जब्त रूसी संपत्तियों से यूक्रेन को युद्ध में मदद की। ❖ **टेक गवर्नेंस का नेतृत्व:** GPAI एवं हिरोशिमा AI प्रोसेस के माध्यम से AI के नैतिक उपयोग का समर्थन। ❖ **ग्लोबल साउथ के साथ सहभागिता**: भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील आदि के साथ सहयोग करता है।
चुनौतियां	**भारत के सामरिक हित**
❖ **आर्थिक प्रभुत्व में कमी:** G7 की वैश्विक GDP में हिस्सा 70% (1980 के दशक) से घटकर लगभग 44% (2021) हो गया। ❖ **सर्वसम्मति की बाधाएं:** संयुक्त घोषणा जारी नहीं होना (2025) ❖ **वैधानिकता का अभाव:** ग्लोबल साउथ का कम प्रतिनिधित्व (भारत और नाइजीरिया शामिल नहीं)।	❖ **संतुलन बनाना**: पश्चिमी देशों और ग्लोबल साउथ में संतुलन (दक्षिण-पश्चिमी देश) ❖ **स्वायत्तता:** ब्रिक्स में अमेरिका की आलोचना या G7 में रूस का विरोध करने से परहेज। ❖ **द्विपक्षीय संबंधों में सुधार:** खालिस्तानी विवाद से परे जाते हुए कनाडा ने 2025 के G7 में सम्मेलन में भारत को निमंत्रण दिया।

निष्कर्ष

G7 विभिन्न मूल्यों पर आधारित मंच बना हुआ है लेकिन आर्थिक प्रभुत्व में गिरावट और महज कुछ देशों के प्रतिनिधित्व की समस्या से जूझ रहा है, जबकि भारत इसका उपयोग रणनीतिक संतुलन के लिए करता है।

2.12. नाटो (NATO)

यूरोप के लिए निहितार्थ	भारत के लिए सामरिक अवसर
❖ **बढ़ती सुरक्षा चिंताएं:** रूस नाटो के विस्तार को अस्थिरता पैदा करने वाला तथा संघर्ष को बढ़ाने वाला मानता है। ❖ **आर्थिक बोझ बढ़ना**: रक्षा पर बजटीय आवंटन बढ़ाने को लेकर यूरोपीय संघ में मतभेद गहरा गया है।	❖ **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** हिंद-प्रशांत पर नाटो का फोकस **क्वाड/भारत के हितों के अनुरूप** है। ❖ **प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंध:** नाटो के विज्ञान और शांति-सुरक्षा (SPS) कार्यक्रम, अंतरिक्ष अभियानों (2024 स्पेस सिंपोजियम) आदि के माध्यम से सहयोग। ❖ **मूल्य आधारित समन्वय:** लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना, आतंकवाद-रोधी प्रयासों को समर्थन देना।

भारत के लिए चुनौतियां
संतुलनकारी भूमिका: नाटो के साथ रूस के संबंधों में सामंजस्य आवश्यक है। स्वायत्तता संबंधी चिंताएँ: अत्यधिक निर्भरता गुटनिरपेक्षता की कूटनीति को कमजोर कर सकती है।

आगे की राह

- **क्वाड-नाटो के बीच समन्वय:** संयुक्त हिंद-प्रशांत अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना।
- **जलवायु संकट -साइबर अटैक से निपटने पर फोकस:** यह नाटो 2022 रणनीतिक अवधारणा के अनुरूप है।

निष्कर्ष

भारत को नाटो के चीन-विरोधी रुख का लाभ उठाते हुए बहुध्रुवीय संबंधों को जारी रखने हेतु अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिए।

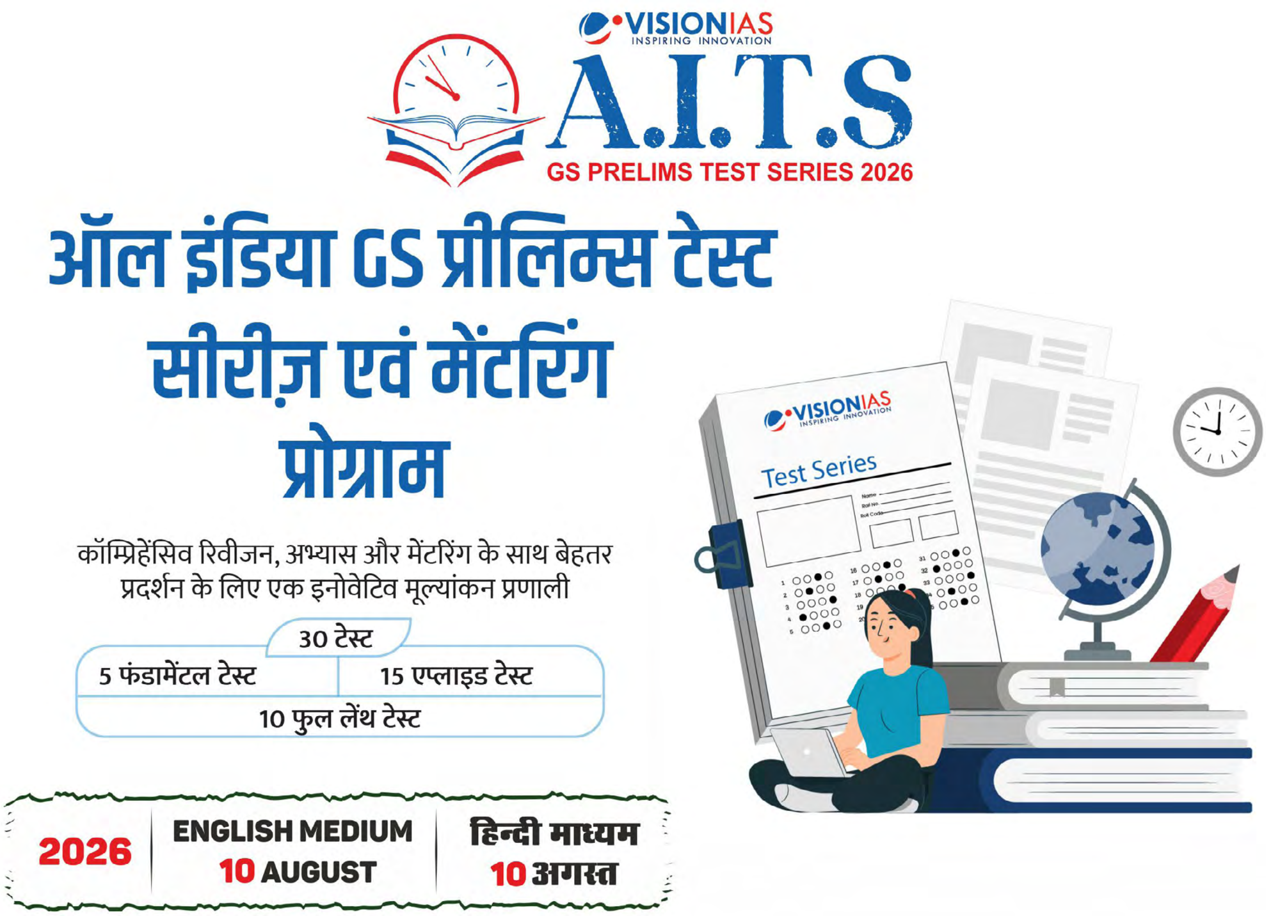

3. भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध (INDIA AND ITS NEIGHBOURHOOD RELATIONS)

3.1.भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (India's Neighbourhood First Policy)

मुख्य उपलब्धियां	सामरिक महत्व
❖ **कनेक्टिविटी:** मोंगला बंदरगाह तक पहुंच (बांग्लादेश), अखौरा-अगरतला रेल लिंक, अफगानिस्तान में INSTC, आदि। ❖ **कूटनीति:** प्रधान मंत्री की 2014 में नेपाल यात्रा (17 वर्षों बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा) ❖ **मानवतावादी नेतृत्व:** वैक्सीन मैत्री (मालदीव और भूटान को सबसे पहले वैक्सीन प्रदान की गई थी) ❖ **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत-बांग्लादेश-नेपाल त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता।	❖ **आर्थिक एकीकरण:** दक्षिण एशिया का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार क्षमता मात्र 5% है। ❖ **सुरक्षा बफर:** आंतरिक सुरक्षा के लिए स्थिर पड़ोसी देश का होना महत्वपूर्ण है। ❖ **सॉफ्ट पावर:** साझा इतिहास लोगों के बीच मजबूत एकरूपता सुनिश्चित करता है।

चुनौतियां

- **चीन के BRI का विस्तार:** हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका), नेपाल और बांग्लादेश में BRI का विस्तार।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** मालदीव का चीन समर्थक रुख, म्यांमार में तख्तापलट, तालिबान का सत्ता पर कब्जा
- **धारणा संबंधी मुद्दे:** 2015 में नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी के बाद हुई प्रतिक्रिया, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी (माले ब्रिज निर्माण)
- **अनसुलझे विवाद:** तीस्ता नदी (बांग्लादेश), कालापानी (नेपाल)।

आगे की राह

- **संकट में सहायता:** अस्थिरता के दौरान मानवीय सहायता (जैसे, श्रीलंका संकट)
- **ट्रैक-II कूटनीति:** "बिग ब्रदर" वाली छवि को सुधारने के लिए नागरिक समाज को शामिल करें
- **व्यापार को बढ़ावा:** SAFTA को पुनर्जीवित करें , कनेक्टिविटी परियोजनाओं को फ़ास्ट ट्रैक करना

निष्कर्ष:

NFP भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व का आधार है , लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और क्षेत्रीय अस्थिरता से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेज़ कार्यान्वयन और विश्वास निर्माण उपायों को प्राथमिकता देनी होगी।

3.2. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष (India-75 Years of India-China Relations)

वर्तमान संदर्भ	शांतिपूर्ण भारत-चीन संबंधों का महत्व
❖ **प्रतीकात्मकता:** "ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो" शब्दावली का उपयोग चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों के विजन को व्यक्त करता है। ❖ **व्यापार संबंध:** चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (118.4 अरब डॉलर)। लेकिन व्यापार घाटा बढ़कर 85 अरब डॉलर (2023-24) हो गया ❖ **रणनीतिक मूल्य:** ब्रिक्स और SCO में सहयोग, वैश्विक संस्थाओं में सुधार करना।	❖ **क्षेत्रीय शांति:** LAC पर विवादों के कारण तनाव कम करना, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा। ❖ **आर्थिक अंतर्निर्भरता:** चीन भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए 90% APIs का मुख्य स्रोत, तकनीक/सौर ऊर्जा के लिए दुर्लभ मृदा की आपूर्ति करता है। ❖ **वैश्विक चुनौतियाँ:** जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य पर संयुक्त कार्रवाई।

प्रमुख चिंताएँ

- सीमा विवाद: 3,488 किलोमीटर लंबी LAC) पर विवादों के कारण झड़पें हुई (डोकलाम 2017, गलवान 2020)
- चीन-पाकिस्तान गठजोड़: PoK से होकर गुजरने वाला CPEC, बांग्लादेश/अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन
- भारत की उपस्थिति: "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" (मालदीव, श्रीलंका), ब्रह्मपुत्र पर बांध निर्माण
- व्यापार असंतुलन: सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर चीन की अत्यधिक निर्भरता

आगे की राह

- राजनयिक संवाद बनाए रखना: वार्ता के लिए G20, SCO से संवाद
- आर्थिक विविधीकरण: API/अर्धचालक पर निर्भरता कम करना
- CBMs: हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का विस्तार
- सामरिक स्वायत्तता: क्वाड/ इंडो-पैसिफिक गठबंधनों के साथ संतुलन बनाए रखना

निष्कर्ष:

यद्यपि भारत "शांतिपूर्ण सीमाओं" की बात करता है, लेकिन चीन के आक्रामक उभार के बीच भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लानी चाहिए।

3.2.1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China-Pakistan Economic Corridor: CPEC)

हालिया विकास	CPEC के बारे में

• **CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार:** चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौते से क्षेत्रीय चिंताएं बढ़ीं
• **नए समझौते:** CPEC के अंतर्गत सहयोग में तेजी लाने के लिए छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
	• **BRI फ्लैगशिप:** 62 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, शिनजियांग से ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
	• **दोहरे मार्ग:**
	  ◦ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (भूमि: चीन को मध्य एशिया से और आगे यूरोप से जोड़ना)
	  ◦ मैरीटाइम सिल्क रोड (समुद्र: चीन-दक्षिण-पूर्व एशिया-अफ्रीका-यूरोप)
	• **संप्रभुता का उल्लंघन:** CPEC भारत की सहमति के बिना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है।

भारत के लिए खतरा	CPEC के प्रत्युत्तर में भारत द्वारा उठाए गए कदम
• **रणनीतिक घेराबंदी:** यह चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान गठजोड़ को मजबूत कर सकता है, चाबहार पोर्ट और INSTC जैसी परियोजनाओं को कमजोर कर सकता है। • **सुरक्षा संबंधी जोखिम:** तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान की भूमि भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। • **आर्थिक लाभ:** CPEC का बुनियादी ढांचा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सैन्यीकृत कर सकता है।	• **चाबहार बंदरगाह:** पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक पहुँच का मार्ग प्रदान करना। • **INSTC:** ईरान और रूस के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने वाला एक मल्टी-मॉडल परिवहन मार्ग। • **IMEC:** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से CPEC को काउंटर करना। • **क्वाड गठबंधन:** एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोगात्मक रुख अपनाना; BRI पर अंकुश लगाना।

निष्कर्ष

CPEC का अफ़ग़ानिस्तान में विस्तार भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए खतरा है, ऐसे में भारत को चाबहार-INSTC एकीकरण, IMEC और क्वाड साझेदारियों को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, ताकि अपने पड़ोसी देशों में चीन की BRI महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला किया जा सके।

3.3. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty)

हालिया विकासक्रम	IWT के बारे में (1960)
❖ **भारत का निर्णय:** जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तौर पर सीमा-पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता तब तक सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित रखा जाएगा। ❖ **पाकिस्तान पर प्रभाव:** पाकिस्तान की 80% खाद्य फसलों, लगभग 5 अरब डॉलर के कृषि निर्यात और ऊर्जा सुरक्षा को खतरा।	❖ **नदी जल के बंटवारे के प्रावधान:** ‣ **पूर्वी नदियां** (रावी, ब्यास और सतलुज): **भारत द्वारा** इन नदियों के समस्त जल का उपयोग करना। ‣ **पश्चिमी नदियाँ** (सिंधु, झेलम, चिनाब): **पाकिस्तान** को आवंटित किया गया है; भारत को विशिष्ट गैर-उपभोग उद्देश्य से कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति प्राप्त है। ❖ **विवाद समाधान तंत्र:** ‣ स्थायी सिंधु आयोग (PIC) ‣ तटस्थ विशेषज्ञ (विश्व बैंक द्वारा नियुक्ति) ‣ मध्यस्थता न्यायालय (CoA) (सात सदस्यों वाला अस्थायी मध्यस्थता अधिकरण)

महत्वपूर्ण मुद्दे	रणनीतिक संदेश
❖ **पाकिस्तान का उल्लंघन:** भारत की किशनगंगा/रतले बांध परियोजना पर पाकिस्तान ने तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र को दरकिनार करते हुए सीधे स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) में मामले को ले गया। ❖ **जैव विविधता पर प्रभाव:** शाहपुरकंडी/ उझ बांध परियोजनाओं से सिंधु नदी डॉल्फिन और उनका पर्यावास प्रभावित हो सकते हैं। ❖ **आतंकवाद से संबंध:** भारत का रुख: "पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते" (2016 के उरी हमले के बाद)	❖ **निलंबन का अर्थ संधि समाप्ति नहीं है:** संधि को रद्द किए बिना राजनीतिक लाभ उठाने का संकेत। ❖ **आगे की राह:** पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए शर्तों पर पुनः बातचीत हो सकती है या डेटा साझा करना रोका जा सकता है।

निष्कर्ष:

सिंधु जल संधि को निलंबित करना भारत की व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है—किसी भी संधि की सफलता के लिए विश्वसनीय साझेदार आवश्यक होते हैं। भारत अपनी जल-कूटनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ा रहा है।

3.3.1. शिमला समझौता (Shimla Agreement)

शिमला समझौते का महत्व	निलंबन का प्रभाव
❖ **कूटनीतिक फ्रेमवर्क के रूप में द्विपक्षीय समाधान:** कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों का मुकाबला करना। ❖ **शिमला समझौते के फलस्वरूप LoC को औपचारिक रूप दिया गया।** ❖ **सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक सहयोग एवं आदान-प्रदान की संभावनाएं:** जैसे करतारपुर गलियारा, नया वीज़ा समझौता 2012, आदि। ❖ **विश्वास और संवाद का पुनर्निर्माण:** आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प।	❖ **प्रतीकात्मक झटका:** कारगिल युद्ध या पुलवामा आतंकी हमले के बाद और कमजोर। ❖ **सुरक्षा जोखिम:** पाकिस्तान द्वारा LoC को वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता न देने से यथास्थिति को बदलने के प्रयास हो सकते हैं। ❖ **कूटनीतिक परिणाम:** पाकिस्तान की अविश्वसनीयता संबंधी भारत के रुख की पुष्टि। ❖ **रणनीतिक अवसर:** भारत सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ अधिक कठोर रुख अपना सकता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर अपने दावों पर नए सिरे से फैसला ले सकता है।

निष्कर्ष

हालाँकि संधि का निलंबन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती हो सकता है, फिर भी भारत नैतिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत आधार पर खड़ा रहते हुए द्विपक्षीय संवाद या आवश्यक सख्त कदम उठाने के लिए विवेकपूर्ण स्थिति में है।

3.4. भारत-श्रीलंका संबंध (India – Sri Lanka Relations)

रणनीतिक साझेदारी	आर्थिक संबंध
❖ **राजनीतिक समर्थन:** ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए श्रीलंका के आवेदन का भारत ने समर्थन दिया है; श्रीलंका ने UNSC में अस्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। (2028-29) ❖ **संयुक्त अभ्यास:** (SLINEX और मित्र शक्ति); मिलन/ MILAN (नौसैनिक अभ्यास) में भाग लिया। ❖ **बहुपक्षीय संबंध:** दोनों देश राष्ट्रमंडल समूह, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और बिम्सटेक के सदस्य हैं।	❖ **सबसे बड़ा साझेदार:** भारत, श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है; श्रीलंका में सबसे अधिक पर्यटक भारत से आते हैं। ❖ **संकट में सहायता:** 4 बिलियन डॉलर की सहायता (2022-23), 2.9 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज की मंजूरी (2023) में सहयोग किया। ❖ **अवसंरचना: कांकेसंथुराई बंदरगाह** के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है।

चुनौतियां

- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** चीन हंबनटोटा बंदरगाह जैसी परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहा है। इससे ऋण-जाल की चिंता के बढ़ने की आशंका है।
- **मछुआरों के बीच विवाद:** श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा बॉटम ट्रॉलर के उपयोग का विरोध करता रहा है। `इसके अलावा, **कच्चातिवु द्वीप** की संप्रभुता को लेकर भी क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो जाता है।
- **तमिल नृजातीय मुद्दा:** इससे श्रीलंका के संविधान में **13वें संशोधन** {इंडो-लंका समझौते (1987)} को लागू करने में देरी।

आगे की राह

- **5S फ्रेमवर्क:** सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति; तथा सार्वभौमिक समृद्धि।
- **विवादों का समाधान:** मछुआरों से जुड़े विवाद पर एक **स्थायी द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र** स्थापित करना चाहिए; तमिल अधिकारों पर संवाद।
- **सॉफ्ट पावर:** बौद्ध सर्किट और रामायण ट्रेल के तहत धार्मिक पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष:

साझा इतिहास और संकट के समय किया गया सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूती देता है, लेकिन संबंधों को स्थायी बनाने के लिए चीन के प्रभाव को संतुलित करना और पुराने विरासत संबंधी मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है।

3.5. भारत-अफगानिस्तान संबंधों में बदलाव (Shift in India-Afghanistan Relations)

भारत की कूटनीतिक नीति में बदलाव क्यों?	चुनौतियां
❖ **भू-राजनीतिक अवसर: अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंधों में तनाव** (हवाई हमले) ने भारत के लिए रास्ता खोला ❖ **चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना:** BRI परियोजनाओं के माध्यम से बीजिंग के एकाधिकार को रोकना। ❖ **सुरक्षा और संपर्क: मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी** को चाबहार-INSTC के माध्यम से मजबूत करने में मदद करना। ❖ **निवेश की सुरक्षा:** बांधों, स्कूलों, संसद भवन में 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश।	❖ **तालिबान का मानवाधिकार रिकॉर्ड:** महिलाओं की शिक्षा/ काम पर प्रतिबंध ❖ **आतंकवाद के खतरे:** हक्कानी नेटवर्क का भारत विरोधी झुकाव, मादक पदार्थों की तस्करी (डेथ क्रिसेंट) ❖ **चीन का बढ़ता प्रभाव:** तालिबान के बीजिंग के साथ बढ़ते संबंध
भारत के लिए सामरिक महत्व	
❖ **मध्य एशिया का प्रवेशद्वार:** TAPI पाइपलाइन और व्यापार गलियारों के लिए महत्वपूर्ण ❖ **सीमा सुरक्षा:** अफगानिस्तान में स्थिर सरकार जम्मू-कश्मीर/पंजाब के पास आतंकवादी केंद्रों को कम करके बेहतर तरीके से निपट सकती है। ❖ **सॉफ्ट पावर:** अफगान लोगों के साथ ऐतिहासिक संबंध (संयुक्त राष्ट्र समर्थित मानवीय सहायता)	

आगे की राह

- **एक्ट वेस्ट पॉलिसी:** भारत को चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाना चाहिए, INSTC का विस्तार करना चाहिए
- **लक्षित मानवीय सहायता: चीन के BRI को प्रतिसंतुलित** करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
- **कूटनीतिक संतुलन:** तालिबान को मान्यता दिए बिना उससे संपर्क बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को बनाए रखना

निष्कर्ष:

भारत की व्यावहारिक भागीदारी का उद्देश्य तालिबान की शासन संबंधी खामियों से निपटते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है।

3.6. भारत-बांग्लादेश संबंध (India-Bangladesh Relations)

बांग्लादेश का सामरिक महत्व	प्रमुख चुनौतियाँ
❖ **आर्थिक साझेदारी:** 2021-22 में व्यापार 18 अरब डॉलर तक पहुंचा, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार। ❖ **कनेक्टिविटी हब:** चटगाँव/मोंगला बंदरगाहों के माध्यम से पूर्वोत्तर तक पहुँच के लिए महत्वपूर्ण ❖ **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** BBIN, बिम्सटेक	❖ **जल विवाद:** तीस्ता नदी जल वितरण पर स्थायी समझौते की कमी ❖ **चीन का बढ़ता प्रभाव:** गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 अभ्यास, ढाका को हथियारों की आपूर्ति ❖ **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा अवैध सीमा पार करना, बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंधों में सुधार ❖ **घरेलू नीतियों का प्रभाव:** CAA/NRC पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया, अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न का खतरा

आगे की राह

- **आर्थिक एकीकरण:** CEPA के लिए शीघ्र बातचीत को शुरू करना, बांग्लादेश द्वारा भारत को दिए गए SEZ का शीघ्र संचालन शुरू करना
- **जल कूटनीति:** तीस्ता के सीमा पार नदी जल प्रबंधन हेतु संयुक्त नदी आयोग का गठन किया जा सकता है।
- **कनेक्टिविटी:** BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करना (निर्यात में 172% की वृद्धि)
- **बहुपक्षवाद:** ढाका के लिए निर्यात में 172% की वृद्धि से BIMSTEC/IORA भूमिका को बढ़ावा देना

निष्कर्ष

मतभेदों के बावजूद, साझा समृद्धि के लक्ष्य – जैसे 'विकसित भारत 2047' और 'स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041' – व्यापार, जल और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नए सिरे से सक्रिय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

3.7. भारत-नेपाल संबंध (India-Nepal Relations)

सामरिक महत्व	हाल के पिघलना प्रयास
❖ **असैन्य संबंध:** "रोटी-बेटी का नाता" (सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध) ❖ **संसाधन में साझेदारी:** कोसी/गंडक/महाकाली संधियाँ जल बंटवारे को नियंत्रित करना ❖ **ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी:** सीमा-पार रेल लिंक के संचालन की; **शुरुआत:** जयनगर (बिहार) से कुर्था (नेपाल) तक। ❖ **रक्षा सहयोग:** संयुक्त सूर्य किरण सैन्य अभ्यास	❖ **छठा संयुक्त आयोग (2024):** बिजली, पर्यटन, जल संसाधनों पर ध्यान केंद्रित ❖ **सॉफ्ट पावर पुश:** लुम्बिनी में बौद्ध विहार, सामुदायिक परियोजनाएँ ❖ **आर्थिक जीवनरेखा:** भारत नेपाल के व्यापार घाटे का 80% वहन करता है
प्रमुख चुनौतियाँ	
❖ **चीन का बढ़ता प्रभाव:** BRI परियोजनाएँ, नेपाल की BRI सदस्यता (2017) में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप। ❖ **सीमा विवाद:** कालापानी /लिपुलेख तनाव का आक्रामक रुख। ❖ **1950 संधि गतिरोध:** नेपाल ने संशोधन की मांग की, "बिग ब्रदर" की धारणा उपयोग किया ❖ **अनियमित सीमाएँ:** स्थानीय उद्योगों और सुरक्षा पर दबाव	

आगे की राह

- **आर्थिक:** विशेष आर्थिक क्षेत्रों, जलविद्युत निवेश के माध्यम से व्यापार घाटे को कम करना
- **संपर्क:** रक्सौल -काठमांडू रेल मार्ग में तेजी , BBIN मोटर वाहन समझौता
- **कूटनीति:** 1950 की संधि में संशोधन
- **बहुपक्षवाद:** बिम्सटेक और सार्क आदि का उपयोग साझा हितों की पूर्ति हेतु करना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत के लिए नेपाल 'पुण्य भूमि' है, जिसकी पवित्र भौगोलिक संरचना उपमहाद्वीप की आध्यात्मिक विरासत का जीवित भंडार है। नेपाल के लिए भारत विशाल आर्थिक क्षेत्र है और आर्थिक कूटनीति और जन-प्रथम संपर्क के माध्यम से चीन के प्रभाव का मुकाबला करना चाहिए।

3.8. भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relations)

भू-रणनीतिक महत्व	आर्थिक और राजनीतिक संबंध
❖ **समुद्री जीवनरेखा:** भारत का लगभग 50 प्रतिशत विदेशी व्यापार और उसका 80 प्रतिशत ऊर्जा आयात समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) के माध्यम से ही होता है। ❖ **सुरक्षा बफर:** चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (जैसे, **सिनामाले ब्रिज का निर्माण)** का मुकाबला करता है ❖ **नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी:** सागर/महासागर विजन का प्रमुख हितधारक	❖ **व्यापार में उछाल:** 1 बिलियन डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार(2023), लोकप्रिय पर्यटन स्थल ❖ **संकट में सहायता: ऑपरेशन कैक्टस (1988) के तहत** भारतीय सेना ने मालदीव में तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दिया; कोविड 19 के दौरान वित्तीय सहायता

चुनौतियां
❖ **भारत विरोधी भावना:** "इंडिया आउट" अभियान, उथुरु थिला फाल्हू - द्वीप हार्बर परियोजना ❖ **चीन की घुसपैठ:** BRI ऋण जाल, बुनियादी ढांचे का प्रभुत्व ❖ **कट्टरपंथी:** ISIS में भर्ती के जोखिम

आगे की राह

❖ **अवसंरचना:** ग्रेट माले कनेक्टिविटी परियोजना को गति देना
❖ **सुरक्षा:** नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ाना, आतंकवाद-रोधी खुफिया जानकारी साझा करना
❖ **सॉफ्ट पावर:** प्रवासी समुदाय, बॉलीवुड, चिकित्सा पर्यटन का लाभ उठाएँ
❖ **ऋण कूटनीति:** BRI ऋणों का मुकाबला करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करना

निष्कर्ष:

चीन की छाया के बावजूद,भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। यह **भारत की 'पड़ोसी पहले नीति की "मजबूत अभिव्यक्ति"** है।

3.9. भारत-भूटान संबंध (India-Bhutan relations)

रणनीतिक साझेदारी	आर्थिक और विकासात्मक सहायता
❖ **संधि-आधारित संबंध:** 1949 मैत्री संधि (2007 में अपडेट) संबंधों का आधार बनी ❖ **सुरक्षा कवच:** 2017 डोकलाम गतिरोध ने भूटान की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया ❖ **जलविद्युत रीढ़:** संयुक्त परियोजनाएं (चुखा, ताला) भूटान के राजस्व का 70% आपूर्ति करती हैं	❖ **13वीं पंचवर्षीय योजना का समर्थन:** भारत ने भूटान के 2024-29 के लिए को आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम का समर्थन भी किया है। ❖ **अवसंरचना विकास: परियोजना 'दंतक'** के तहत भूटान ने 80% सड़कें बनाईं ❖ **निवेश प्रभुत्व:** भारत **भूटान के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 50%** का योगदान देता है।
उभरती चुनौतियाँ	**आगे की राह**
❖ **चीन का बढ़ता प्रभाव:** ▸ अब भूटान के व्यापार का 25% ▸ 2021 के बॉर्डर रोडमैप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास डोकलाम बफर को खतरा ❖ **सुरक्षा कमजोरियाँ:** ▸ **ULFA/NDFB** उग्रवादी भूटान को अपने छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ▸ पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने BBIN मोटर वाहन समझौते को रोक दिया है।	❖ **तकनीकी साझेदारियां:** फिनटेक, अंतरिक्ष, बायोटेक में सहयोग को मजबूत करना चाहिए। ❖ **GNH सिद्धांत के अनुरूप सतत विकास:** गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जैसी खुशहाली अर्थव्यवस्था परियोजनाओं में निवेश करना ❖ **सांस्कृतिक संबंध:** तीर्थयात्रा सर्किट के माध्यम से बौद्ध संबंधों का लाभ उठाएँ ❖ **त्रिपक्षीय वार्ता:** सीमा विवादों से निपटने के लिए भारत, चीन और भूटान के बीच खुले संवाद विकल्प पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष:

साझा सभ्यतागत संबंध इस रिश्ते को एक "स्वाभाविक साझेदारी" का रूप देते हैं, लेकिन भारत को चीन की बढ़ती मौजूदगी का प्रभावी जवाब देने के लिए आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा।

3.10. हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region)

IOR का रणनीतिक महत्व	भारत का IOR नेतृत्व
❖ **आर्थिक जीवनरेखा:** विश्व स्तर पर 1/3 बल्क कार्गो और 2/3 ऑयल शिपमेंट IOR से हो कर गुजरता है। ❖ **चोकपॉइंट्स:** बाब अल-मंडेब, होर्मुज जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे विश्व के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। ❖ **प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र:** नीली अर्थव्यवस्था 2.0 पहलों में योगदान देने के लिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, तेल/गैस भंडार।	❖ **मार्गदर्शक नीति:** सागर (सभी के लिए सुरक्षा और संवृद्धि) द्वारा निर्देशित। ❖ **नौसेना शक्ति:** ‣ समुद्री पायरेसी रोधी अभियान (अदन की खाड़ी), ‣ QUAD के साथ मालाबार युद्ध अभ्यास।

चुनौतियां
❖ **चीन का प्रभाव:** ‣ 350 से अधिक युद्धपोत का बेड़ा (विश्व स्तर पर सबसे बड़ी नौसेना)। ‣ बंदरगाह निवेश (हंबनटोटा, ग्वादर, जिबूती) ❖ **संसाधनों का अभाव:** भारत में 130 युद्धपोत बनाम चीन के युद्धपोत का बेड़ा ❖ **गैर-पारंपरिक खतरे:** पायरेसी की बढ़ती घटनाएं, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद। ❖ **अमेरिकी नीति में बदलाव:** यूक्रेन और मध्य पूर्व संघर्षों के कारण हिंद-प्रशांत पर कम ध्यान।

आगे की राह

- **नौसेना आधुनिकीकरण:** स्वदेशी जहाज निर्माण में तेजी लाना , बेड़े का आकार बढ़ाना
- **द्वीप विकास:** क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप का रणनीतिक केंद्रों के रूप में बेहतर उपयोग करना।
- **क्षमता निर्माण:** तटीय देशों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सैन्य कूटनीति का विस्तार करना।
- **मिनीलेटरल साझेदारी:** क्वाड, IMEC, फ्रांस-UAE-भारत त्रिपक्षीय साझेदारी को मजबूत बनाना।

निष्कर्ष:

भारत का SAGAR विजन और जन-केंद्रित दृष्टिकोण उसे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक विश्वसनीय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं, लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए त्वरित नौसैनिक आधुनिकीकरण और एकीकृत रणनीति अपनाना आवश्यक है।

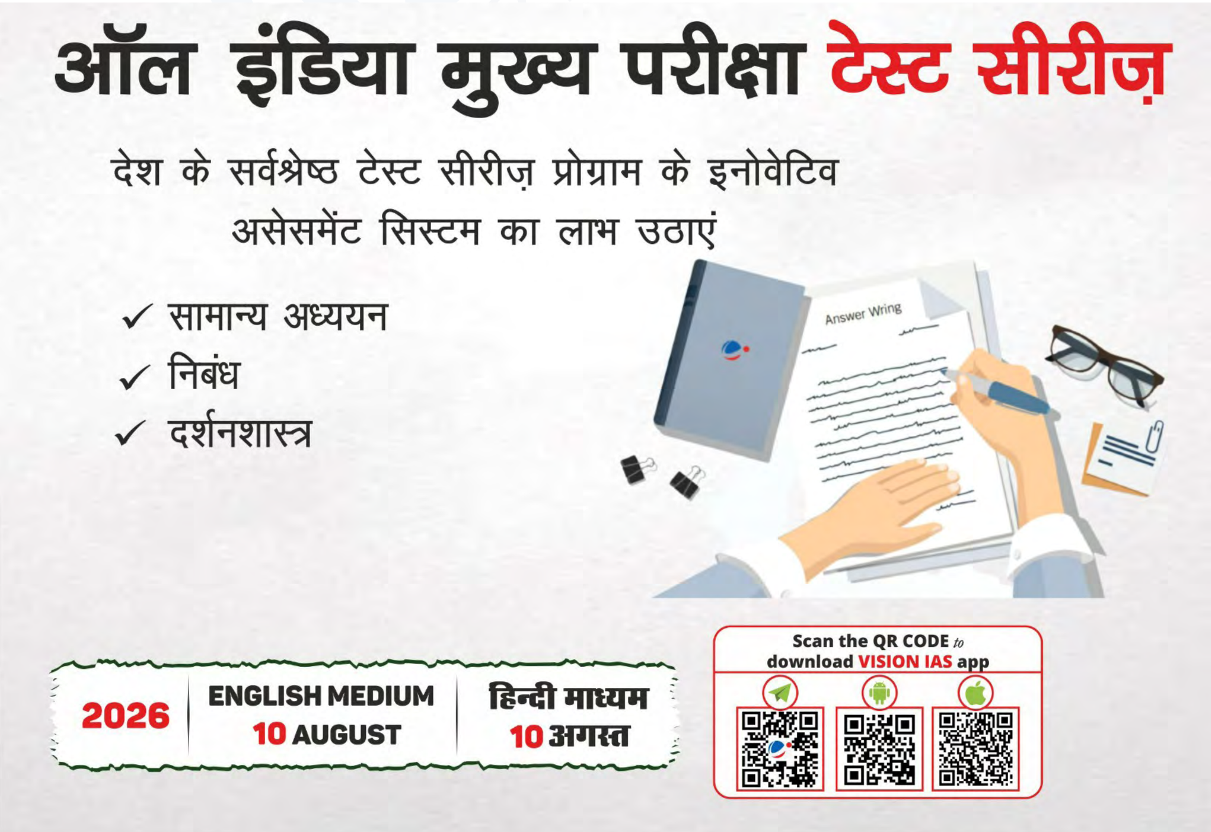

4. भारत से जुड़े और/या भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह और समझौते (BILATERAL GROUPING AND AGREEMENTS INVOLVING INDIA AND/OR AFFECTING India)

4.1. भारत-पश्चिम एशिया (India-West Asia)

भारत का पश्चिम एशिया पॉलिसी फ्रेमवर्क	भारत के लिए रणनीतिक महत्व
❖ भारत खाड़ी क्षेत्र को अपना **'निकटतम पड़ोस' का हिस्सा** मानता है। ❖ **लुक वेस्ट नीति (2005):** यह नीति पश्चिम एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अपनाई गई थी। ❖ भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन के साथ **डी-हाइफनेशन की नीति** अपनाई। ❖ UAE, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान जैसे देशों की यात्रा करना। ❖ **पाकिस्तान फैक्टर:** पुलवामा, बालाकोट और अनुच्छेद 370 के बाद भारत को UAE का समर्थन प्राप्त हुआ।	❖ **UAE:** प्रमुख ऊर्जा भागीदार; 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार; भारत के कुल प्रेषण का प्रमुख स्रोत। ❖ **ईरान:** चाबहार बंदरगाह समझौता, INSTC कनेक्टिविटी, प्रतिबंधों के बावजूद महत्वपूर्ण। ❖ **सऊदी अरब:** लगभग 43 बिलियन डॉलर का व्यापार; ऊर्जा सुरक्षा केंद्र; सुरक्षा सहयोग (उदाहरण के लिए, 26/11 की गिरफ्तारी) ❖ **इजरायल:** रक्षा प्रौद्योगिकी (फाल्कन, BARAK-8); जल और कृषि नवाचार; बहुपक्षीय सहयोग I2U2 की स्थापना। ❖ **कुवैत:** 43 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधान मंत्री की यात्रा; LNG का मुख्य स्रोत।
संबंधों में महत्वपूर्ण चुनौतियां	**आगे की राह**
❖ **व्यापार असंतुलन:** सऊदी अरब व UAE के साथ व्यापार घाटा। ❖ **श्रमिक संबंधी मुद्दे:** कफाला प्रणाली से श्रमिकों का शोषण; प्रवासन संबंधी तनाव। ❖ **सुरक्षा संकट: लाल सागर संकट;** हूती विद्रोहियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन पर हमला।	❖ **तटस्थ कूटनीति:** उभरते गुटों और क्षेत्रीय संघर्षों के बीच संतुलन। ❖ **FTA की प्रक्रिया** को तेज करना: व्यापार समझौतों में तेजी लाना। ❖ **प्रवासन संबंधी अधिकार:** श्रम और मानव संसाधन मुद्दों के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए।

निष्कर्ष

अशांत भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच, पश्चिम एशिया के साथ भारत की संतुलित और बहुपक्षीय कूटनीति ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक साझेदारी और प्रवासी हितों को सुरक्षित रखती है। साथ ही सऊदी अरब, UAE, इज़राइल और ईरान के साथ भरोसेमंद संबंधों को और प्रगाढ़ बना रही है।

4.1.1. पश्चिम एशिया में भारत की संतुलित विदेश नीति (India's Foreign Policy Balancing in West Asia)

पश्चिम एशिया में संकट
❖ योम किप्पुर की वर्षगांठ पर हमास द्वारा इजरायल पर हमले ने **इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध** को और अधिक तीव्र कर दिया। ❖ **हूतियों** ने इजरायल और लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर **हमले** किए। ❖ असद का शासन ध्वस्त हो गया (सीरिया, दिसंबर 2024), जहां प्रमुख शक्तियों ने सीरिया को एक छद्म युद्ध के क्षेत्र में बदल दिया।

भारत पर प्रभाव	वैश्विक स्तर पर प्रभाव
❖ **ऊर्जा सुरक्षा: खाड़ी-पश्चिम एशिया-उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र** भारत के कुल कच्चे तेल आयात में 66% से अधिक का योगदान देता है। ❖ **प्रवासी और विप्रेषण (Remittances):** पश्चिम एशिया में लगभग 8 से 9 मिलियन भारतीय हैं, जिनमें **संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब**,आदि देश भारत को विप्रेषण के शीर्ष स्रोतों में से हैं। ❖ **रणनीतिक परियोजना:** IMEC गलियारा, चाबहार बंदरगाह (ईरान) जैसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन बाधित होगा। ❖ **आर्थिक संबंध: GCC भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार** गुट है। (15.8% की हिस्सेदारी) ❖ **समुद्री मार्ग:** भारत का 80% बाहरी व्यापार प्रमुख जलमार्गों से होकर गुजरता है।	❖ **कूटनीतिक उपलब्धियों के समक्ष खतरा:** अब्राहम एकॉर्ड्स और इजरायल-सऊदी अरब समझौता आदि का खतरे में पड़ना। ❖ **समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां:** नौसैनिक टकराव से हिंद-प्रशांत व्यापार खतरे में पड़ सकता है। ❖ **राष्ट्रों के बीच हथियारों की होड़:** परमाणु हथियारों की होड़ से वैश्विक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। ❖ **वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** कच्चे तेल की उच्च कीमतें खाद्य कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं। साथ ही, अर्थव्यवस्थाओं की रेटिंग भी कम हो सकती है। ❖ **अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संकट:** जानमाल के नुकसान, जबरन विस्थापन, युद्ध अपराध (उदाहरण के लिए- इजरायल का रफाह आक्रमण) ❖ **UN संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्न:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की की प्रभावशीलता की वैश्विक जांच करना।
पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के उपाय	
तत्काल उपाय: UNSC द्वारा पारित **संकल्प 2728** की मांगों को पूरा करना चाहिए। ❖ गाजा में "तत्काल" युद्धविराम का आह्वान किया गया। ❖ **सभी बंधकों की तत्काल रिहाई;** ❖ मानवीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता।	**दीर्घकालिक उपाय: संरचनात्मक सुधार** ❖ सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त क्षेत्र की घोषणा शामिल करना। ❖ द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दों का समाधान करना। ❖ भारत-GCC गुट के साथ आर्थिक और शांति संबंधों को और बेहतर कर सकता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे पश्चिम एशिया संघर्ष की दिशा में बढ़ रहा है, भारत के लिए आवश्यक है कि वह एक क्षेत्रीय संतुलनकारी शक्ति की भूमिका निभाते हुए अपनी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हितों और प्रवासी समुदाय की रक्षा करे। व्यापक भू-राजनीतिक संकट से बचाव के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में शांति प्रयासों का समर्थन और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ संबंधों को और गहराना बेहद आवश्यक हो गया है।

4.2. भारत- जापान संबंध (India-Japan Relations)

सहयोग के मुख्य स्तंभ
❖ **रणनीतिक साझेदारी:** जापान की FOIP रणनीति और भारत की IPOI पहल दोनों के बीच राजनीतिक हस्तक्षेप। ❖ **आर्थिक संबंध:** दोनों देशों के बीच लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार, जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। ❖ **अवसंरचना विकास:** मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जैसी परियोजनाओं पर सहयोग। ❖ **रक्षा संबंध: सामान्य सैन्य अभ्यास** (धर्म गार्डियन, जिमेक्स/ JIMEX) और ACSA लॉजिस्टिक पैक्ट। ❖ **प्रौद्योगिकी:** इसरो और JAXA का संयुक्त **अंतरिक्ष मिशन (LUPEX),** औद्योगिक साझेदारी

चुनौतियां	आगे की राह
❖ CEPA के बाद भी भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार सीमित बना हुआ है। ❖ चीन और रूस का अलग-अलग दृष्टिकोण। ❖ मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी।	❖ आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। ❖ रक्षा सहयोग प्रौद्योगिकी में सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ❖ क्वाड, जी20 में बहुपक्षीय रणनीतियों के बीच सहयोग को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष

यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।

4.3. भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया (India and South East Asia)

मलेशिया	इंडोनेशिया
❖ **एनहैंस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप** से **कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप** में अपग्रेड। ❖ **इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)** में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ❖ **समुद्री संचार मार्गों (SLOC) को सुरक्षित करना:** सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरूमध्य से इसकी निकटता। ❖ **ऑयल पाम कूटनीति** (भारत कुल ऑयल पाम आयात का एक-तिहाई आयात करता है।) ❖ **प्रवासी समुदाय:** तीसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय मलेशिया में है।	❖ दोनों देश रामायण और महाभारत के साथ प्राचीन **सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संबंध साझा** करते है। ❖ दोनों **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)** के संस्थापक देश हैं। ❖ **सुरक्षा एवं रक्षा:** द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास **गरुड़ शक्ति।** ❖ **कनेक्टिविटी:** इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्राएंगल (IMT-GT)
वियतनाम	**थाईलैंड**
❖ **कार्य योजना (2024-2028):** व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए। ❖ **भारत** ने वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्रेडिट लाइन को बढ़ाकर **300 मिलियन अमेरिकी डॉलर** कर दिया है। ❖ **सांस्कृतिक सहयोग:** यूनेस्को विश्व विरासत स्थल **"माय सन"** मंदिर परिसर का पुनरुद्धार करना। ❖ **रक्षा सहयोग:** PASSEX, VINBAX और MILAN जैसे सैन्य अभ्यास शामिल।	❖ **दोनों देशों के बीच** रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई। ❖ **पारस्परिक रूप से इंडो प्रशांत लक्ष्य:** दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले, पारदर्शी, नियम आधारित, समावेशी और लचीले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को महत्त्व देते हैं। ❖ **बिम्सटेक** जैसे मंचों में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है।

सिंगापुर
❖ **रणनीतिक और आर्थिक सहयोग:** व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2015)। ❖ **आसियान** समूह में भारत का **सबसे बड़ा व्यापारिक** साझेदार। ❖ **फिनटेक और नवाचार:** RuPay-PayNow लिंकेज। ❖ **डायस्पोरा:** सिंगापुर की आबादी में लगभग 9.1% भारतीय मूल के लोग हैं। ❖ **सेमीकंडक्टर आपूर्ति:** विश्व आपूर्ति का 10% तक। ❖ **रक्षा एवं सुरक्षा:** सिम्बेक्स जैसे **संयुक्त युद्ध अभ्यास।**

निष्कर्ष

भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध बहुत पुराने व गहरे हैं, जो उनके समकालीन संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। **धर्म, संस्कृति, स्थापत्य और आध्यात्मिक क्षेत्रों** को समेटे हुए **अतीत के संबंधों के समृद्ध संदर्भ** ही वे पहलू हैं, जो समकालीन विश्व व्यवस्था में दोनों पक्षों के बीच संबंधों को अद्वितीय एवं विशिष्ट बनाते हैं।

4.3.1. भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष (10 Years of India's Act East Policy)

एक्ट ईस्ट नीति (AEP) की प्रभावशीलता	रणनीतिक हितों में कन्वर्जेंस या तालमेल
❖ **पूर्वी एशिया से लेकर हिंद-प्रशांत तक AEP का विस्तार:** लुक ईस्ट नीति पूरी तरह से **आसियान** पर केंद्रित थी। जो अब **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विजन** का विस्तार किया गया है। ❖ **बहुपक्षीय समझौते:** आसियान, बिम्सटेक, ACD, IORA आदि के साथ गहन साझेदारी। ❖ **संस्थागत सहयोग में वृद्धि:** संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगियों के साथ संस्थागत सहयोग। **उदाहरण के लिए-** भारत IPEF, SCRI आदि में शामिल हुआ।	❖ **क्षेत्रीय साझेदारी:** भारत ने **इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया** के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। ❖ **भारत और ताइवान संबंध:** अनौपचारिक संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति करना। ❖ **रणनीतिक अनुरूपता: जापान के FOIP, कोरिया के NSP, आसियान के AIOP के साथ समानताएं**

AEP के कार्यान्वयन के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां
❖ **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में देरी:** कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना में देरी और प्रारंभिक लागत में बढ़ोतरी। ❖ **शरणार्थियों का जोखिम: पूर्वोत्तर** सीमाओं पर अस्थिरता; **उदाहरण के लिए**- मणिपुर ❖ **चीन की समुद्री उपस्थिति:** बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के माध्यम से सामरिक समुद्री व्यापार मार्गों तक भारत की पहुंच प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- **व्यापार:** बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए ATIGA समझौता।
- **अवसंरचना:** समुद्री परियोजनाओं को जल्द-से-जल्द पूरा करके कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना।
- **सुरक्षा सहयोग:** हिंद प्रशांत महासागर में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** बौद्ध-बहुल देशों के साथ साझा सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाना।

निष्कर्ष

AEP के 10 वर्षों ने व्यापार, सुरक्षा और जलवायु कूटनीति के क्षेत्र में भारत-आसियान संबंधों को और मजबूत किया है। आगे चलकर, बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना और रणनीतिक साझेदारी का विस्तार भविष्य में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है।

4.4. भारत-प्रशांत द्वीपीय देश संबंध (India-Pacific Islands Nations Relations)

भारत के लिए सामरिक महत्व	भारत की प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भागीदारी
❖ **हिंद-प्रशांत विजन:** एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना। ❖ **भू-सामरिक अवस्थिति:** ये भारत की व्यापक समुद्री रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। ❖ **आर्थिक क्षमता को मजबूत करना:** विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में संसाधनों की सुरक्षा तक पहुँच।	❖ 2019 में **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)** लॉन्च किया गया। ❖ **अनुदान सहायता और रियायती लाइन- ऑफ़ क्रेडिट:** नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता। ❖ **चुनाव प्रक्रियाओं को आसान बनाने में मदद:** उदाहरण के लिए- पापुआ न्यू गिनी को अमिट स्याही (indelible ink) की आपूर्ति।
सहयोग में चुनौतियां	
❖ **चीन का बढ़ता प्रभाव:** सामरिक प्रतिस्पर्धा। (उदाहरण के लिए- सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा समझौता)। ❖ **संसाधन संबंधी सीमाएं:** घरेलू आवश्यकताओं के लिए भारत के संसाधन, बाह्य व्यापार में बाधा बनते हैं। ❖ **विशाल भौगोलिक दूरी:** हर बार संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन को कठिन बना देती है।	

आगे की राह

- **राजनयिक वार्ता:** विश्वास को गहरा करने के लिए नियमित आदान-प्रदान।
- **समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण:** अवैध मत्स्यन, समुद्री डकैती (पायरेसी) और समुद्री प्रदूषण जैसे **मुद्दों पर सहयोग** करना।
- **लक्षित प्रोजेक्ट: सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, विलवणीकरण** जैसे क्षेत्रकों में मांग-आधारित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

निष्कर्ष

प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी **पारस्परिक आकांक्षाओं, साझा चुनौतियों और समावेशी वैश्विक दृष्टिकोण** पर आधारित है, जो समानता और सहयोग पर टिकी एक आदर्श वैश्विक साझेदारी की मिसाल पेश करती है।

4.5. भारत और मध्य एशियाई गणराज्यों के संबंध (India and Central Asian Republics Relations)

मध्य एशिया के बारे में	भारत के लिए सामरिक महत्व
❖ **मध्य एशिया (भारत के विस्तारित पड़ोस का एक हिस्सा)** भारत को अपने **राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा पहुंच** का लाभ उठाते हुए यूरेशिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एक सही मंच प्रदान करता है। ❖ **पांच स्थल-रुद्ध देश:** कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान।	❖ **ऊर्जा सुरक्षा:** उदाहरण के लिए- तुर्कमेनिस्तान के पास से गैस पाइपलाइन; कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौता और तापी पाइपलाइन समझौता। ❖ **कनेक्टिविटी:** INSTC और अश्गाबात समझौता। एक पूर्ण कार्यशील INSTC चीन के BRI का जवाब हो सकता है। ❖ **क्षेत्रीय शांति:** CAR की स्थिरता से अफगानिस्तान की सुरक्षा से जुड़ी है
मुख्य चुनौतियां	
❖ **व्यापार अंतराल:** भारत- CAR के बीच लगभग 2 बिलियन डॉलर, जबकि चीन का व्यापार लगभग 100 बिलियन डॉलर है। ❖ **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** रूस और चीन की मौजूदगी के कारण। ❖ **कमजोर कनेक्टिविटी:** सीधे जमीनी संपर्क का अभाव और INSTC की धीमी गति।	

आगे की राह

- **30 साल का विजन प्लान:** लघु, मध्यम और दीर्घकालिक जुड़ाव के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकता है।
- **अपनी क्षमताओं का लाभ उठाना:** ऐसी परियोजनाओं को पूरा करना जिनके स्थायित्व और इष्टतम लागत, दोनों के संदर्भ में दीर्घकालिक लाभ हो।
- **पर्यटन और जन संपर्क:** सांस्कृतिक और लोगों के मध्य बेहतर संपर्क के लिए।

निष्कर्ष

भारत-मध्य एशिया के बीच मजबूत भागीदारी साझा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में **शक्ति गुणक के रूप में कार्य करती है**, जो ऊर्जा, कनेक्टिविटी और यूरेशियन भू-राजनीति पर परिणामों को आकार दे सकती है।

4.6. भारत-अफ्रीका संबंध (India-Africa Relationship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **घाना और नामीबिया सहित कई अफ्रीकी देशों** की यात्रा की, तथा भारत-अफ्रीका संबंधों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत-अफ्रीका संबंधों का महत्व	मुख्य चुनौतियां
❖ **साझा अतीत: उपनिवेशवाद के खिलाफ साझा संघर्ष** और **मिस्र के साथ** गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। ❖ **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** भारत अफ्रीका का **चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है। ❖ **खनिज और ऊर्जा सुरक्षा:** विश्व के खनिज भंडार का **30% अफ्रीका** में है; भारत अपने **कच्चे तेल का लगभग 4% अफ्रीका से आयात** करता है। ❖ **सतत विकास:** भारत ने अफ्रीका को $12 बिलियन का रियायती ऋण प्रदान किया है। प्रमुख पहलों में **ई-विद्याभारती, ITEC, पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क, और व ई-आरोग्यभारती** शामिल हैं।	❖ **परियोजना वितरण में धीमी गति:** चीन से भी धीमी; कृषि व्यवसाय के शोषण के आरोप। कृषि-व्यवसाय फर्मों पर भूमि हड़पने का आरोप। ❖ **चीनी प्रभाव:** अफ्रीका के 20% निर्यात चीन को जाते हैं, जिबूती में सैन्य सुविधा स्थापित की गई। ❖ **निवेश में जोखिम धारणा:** जोखिम का अति-अनुमान और सीमित जागरूकता भारतीय व्यापार में बाधा डालती है

आगे की राह

- **संस्थागत संवाद:** भारत-अफ्रीकी संघ ट्रैक 1.5 संवाद स्थापित करना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: 'ट्रिपल ए' (किफायती/ Affordable, उपयुक्त/ Appropriate व अनुकूलनीय/ Adaptable)** प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए।
- **अभिनव वित्त-पोषण:** मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पेंशन फंड निवेश आदि का पता लगाना चाहिए।

निष्कर्ष

अफ्रीका के साथ हमारी साझेदारी रणनीतिक चिंताओं और आर्थिक लाभों से परे है। यह हमारे साझा **भावनात्मक बंधनों और हमारी एकजुटता** की भावना पर आधारित है, जो एक समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था की नींव रखते हैं।

4.7. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध (India-U.S.A. Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा** की, जिसमें व्यापार, तकनीक, रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

साझेदारी का महत्व	साझेदारी में तनाव पैदा करने वाले मुद्दे
❖ **आर्थिक संबंध:** संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत IPEF के तीन स्तंभों में शामिल हो गया है। ❖ **रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करना:** क्वाड से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी। ❖ **रक्षा आधुनिकीकरण:** 4 मूलभूत रक्षा समझौते ❖ **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** iCET (2023), **आर्टेमिस समझौते** और **NISAR** अंतरिक्ष मिशन। ❖ **ऊर्जा और परमाणु सुरक्षा:** LNG आपूर्तिकर्ता है; एंटिटी लिस्ट से भारतीय संस्थाओं को हटाने के बाद **असैन्य परमाणु समझौते को पुनर्जीवित** किया जा सकता है। ❖ **आतंकवाद से निपटना:** अमेरिका ने **तहव्वुर राणा** (26/11 आतंकी हमलों से जुड़ा आतंकी) के भारत को प्रत्यर्पण को मंजूरी प्रदान की। ❖ **वैश्विक समर्थन: UNSC** में भारत की स्थायी सदस्यता, **NSG** और **IEA** में अमेरिका का समर्थन। ❖ **जलवायु कार्रवाई: SCEP** (2021) और स्वच्छ ऊर्जा पहलों के माध्यम से ❖ **उद्योग: सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट** स्थापित करने हेतु समझौता; ASIA गठबंधन, QUAD आधारित उत्पादन को बढ़ाना। ❖ **सांस्कृतिक:** पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए अपने पहले **'सांस्कृतिक संपदा समझौते'** पर हस्ताक्षर किए।	❖ **व्यापार एवं शुल्क:** GSP सूची निरस्त; भारत 2024 की प्राथमिकता निगरानी सूची में (**IPR** संबंधी चिंताएं) ❖ **भू-राजनीतिक मतभेद: रूस-यूक्रेन** और क्वाड के सैन्यीकरण पर मतभेद

आगे की राह

- ❖ **द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA):** बाजार तक पहुंच और IPR आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी।
- ❖ **रक्षा फ्रेमवर्क:** 2025-35 के रणनीतिक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया गया।

निष्कर्ष

हम अपने अविश्वसनीय लोगों की नवीन भावना से जुड़े हुए और सशक्त हैं और साथ मिलकर, हम जो कार्य करेंगे, उनके माध्यम से हम 21वीं सदी को आकार देंगे।

4.7.1. संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी उपाय (USA'S PROTECTIONIST MEASURES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी **'अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी'** का हवाला देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), पेरिस समझौता तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और हाल ही में **UNESCO** (तीसरा इजराइल विरोधी रुख का हवाला देते हुए बाहर निकलने का फैसला) जैसी **प्रमुख वैश्विक संस्थाओं/ व्यवस्थाओं से अलग होने** का फैसला किया है।

संदर्भ और उदाहरण	संरक्षणवादी कदमों का वैश्विक प्रभाव
❖ **विश्व स्वास्थ्य संगठन से निकासी (2020)** और वापसी (2021) ❖ **पेरिस समझौते से अलग होने का फैसला (2017)**, पुनः शामिल (2021) ❖ **TPP से निकासी (2017)**; **NAFTA** की जगह **USMCA** ने ले ली।(2020) ❖ **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** में नियुक्तियों को बाधित करके उसे निष्क्रिय बनाना।	❖ **बहुपक्षीय संस्थाओं का कमजोर होना:** अमेरिका के 'अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति संप्रभुतावादी विचार कारण। ❖ **वैश्विक अनुसंधान के लिए खतरा: WHO महामारी समझौते** में संशोधन पर वार्ता रोक दी गई। ❖ 2022-2023 में **WHO के कुल राजस्व के 15.6%** में अमेरिकी अंशदान था।

भारत पर प्रभाव	
सकारात्मक प्रभाव	**नकारात्मक प्रभाव**
❖ **सामरिक लाभ:** अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव की वजह से IT सेवाएँ, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों के लिए भारत एक निवेश हब के रूप में उभर सकता है। ❖ **हिंद-प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी: क्वाड (QUAD), IMEC, IPEF** जैसी पहलों के तहत रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है। ❖ **प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण: iCET** और असैन्य परमाणु ऊर्जा साझेदारी जैसी पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा।	❖ **निर्यात का दबाव:** भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ; चीनी निर्यात से प्रतिस्पर्धा। ❖ **आव्रजन पर प्रतिबंध:** H1-B वीजा को सीमित करने से भारतीय तकनीकी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। ❖ **'बाय अमेरिकन' नीति:** भारतीय बाजार तक **पहुंच को प्रतिबंधित** करता है। इससे **मेक इन इंडिया पहल** और **PLI योजना** आदि पर भी असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष

अमेरिका का बहुपक्षवाद से पीछे हटना **वैश्विक संस्थाओं को कमजोर** करता है, लेकिन भारत के लिए **रणनीतिक अवसर** भी पैदा करता है। नई दिल्ली को संरक्षणवादी व्यापार और आव्रजन नीतियों से बचाव करते हुए इस बदलाव का लाभ उठाना चाहिए।

4.8. भारत-कनाडा संबंध (India-Canada Relationship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और कनाडा ने एक-दूसरे की राजधानियों में **उच्चायुक्तों** की पुनः नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। यह लगभग दो वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद **कूटनीतिक संबंधों में सामान्यीकरण** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हालिया टकराव के लिए जिम्मेदार कारण	भारत-कनाडा संबंधों का महत्व
❖ **खालिस्तानी अतिवाद:** इन गतिविधियों को कनाडा द्वारा समर्थन और सुरक्षित आश्रय प्रदान करना। ❖ **सुरक्षा मामलों में सहयोग की कमी:** प्रत्यर्पण अनुरोधों व आतंकवाद के मामलों की उपेक्षा)। ❖ **व्यापार में गतिरोध:** CEPA वार्ताएं स्थगित हो गई। ❖ **वोट बैंक की राजनीति** - कनाडा में सिख समुदाय का राजनीतिक इस्तेमाल।	❖ **रणनीतिक सहयोग:** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था (चीन कारक)। ❖ **आर्थिक:** 2023 में 19 बिलियन डॉलर से अधिक का (वस्तुएं+सेवाएं) द्विपक्षीय व्यापार हुआ। ❖ **निवेश:** कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारत में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। ❖ **भारतीय प्रवासी समुदाय:** कनाडा में लगभग 18 लाख भारतीय रहते हैं। ❖ **रक्षा सहयोग:** DRDO और कनाडाई वाणिज्यिक निगम के बीच रक्षा तकनीक हेतु समझौता हुआ है।
राजनयिक तनाव के संभावित प्रभाव	**संबंधों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम**
❖ **व्यापार और निवेश में रुकावट:** CEPA और व्यवसाय विश्वास में देरी। ❖ **भारतीय प्रवासियों की चिंता:** विशेषकर कनाडा में अनुमानित संख्या 2.3 लाख भारतीय छात्र प्रभावित हुए। ❖ **वीजा संबंधी मुद्दे:** प्रक्रिया में जटिलताएं/ देरी होना।	❖ **राजनयिक संवाद:** उच्च-स्तरीय चर्चा फिर से शुरू करनी चाहिए। ❖ **आतंकवाद के खिलाफ सहयोग:** आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा फ्रेमवर्क 2018 को लागू करना चाहिए। ❖ **व्यापारिक वार्ताएं:** CEPA के अंतर्गत वार्ता पुनः शुरू करनी चाहिए।

निष्कर्ष

तनाव के बावजूद, भारत-कनाडा संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मजबूत जनसंपर्क और बढ़ते आर्थिक सहयोग पर आधारित हैं।

4.9. भारत-यूरोप संबंध (India-Europe)

4.9.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-United Kingdom Relations)

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों के बीच बढ़ती घनिष्ठता

- **रणनीतिक साझेदारी:** 2021 में संबंधों को **व्यापक स्तर** तक बढ़ा दिए गए।
- **रक्षा संबंध: संयुक्त सैन्य अभ्यास -** अजेय वारियर, कोंकण, कोबरा वारियर।
- **स्वास्थ्य सहयोग:** एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन सहयोग।
- **व्यापार और निवेश:** यूनाइटेड किंगडम भारत में **छठा सबसे बड़ा निवेशक** है, भारत **यूनाइटेड किंगडम का 12वां** सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- **प्रौद्योगिकी साझेदारी:** 2024 में **प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI)** शुरू की थी।

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों का बढ़ता महत्व	भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों में चुनौतियां
• **विज़न 2035 फ्रेमवर्क:** बहु-स्तरीय संबंधों का और गहन बनाने के लिए रोडमैप 2030 के स्थान पर विस्तारित फ्रेमवर्क जारी किया। • **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा:** भारत- UK समग्र सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा रहे हैं। • **IOR पर ध्यान केंद्रित करना:** हिंद महासागर क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम के कम-से-कम 7 स्थायी सैन्य अड्डे हैं।	• **औपनिवेशिक प्रभाव:** उपनिवेशवाद-विरोधी रुख भारत की सामरिक क्षमता को सीमित करता है। • **सुरक्षा में कमी:** भारतीय ध्वज के साथ अपमानजनक व्यवहार और भारत विरोधी प्रदर्शनों से निपटने में विफलता।

निष्कर्ष

यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के संबंध पारंपरिक रूप से अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंधों की तुलना में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक सहयोग से भारत के साथ संबंधों में लगातार सुधार हुआ है।

4.9.1.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम विज़न 2035 तथा व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता {India-UK Vision 2035 and Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)}

भारत-UK विज़न 2035	CETA की प्रमुख विशेषताओं पर एक नजर

• **व्यापार एवं आर्थिक विकास: CETA** पर हस्ताक्षर तथा **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)** की दिशा में कार्य।
• **प्रौद्योगिकी और नवाचार: UK-भारत अनुसंधान और नवाचार** कॉरिडोर की स्थापना।
• **रक्षा एवं सुरक्षा: JEACT और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन** का संयुक्त विकास; **हिंद-प्रशांत** क्षेत्र पर रणनीतिक सहयोग।
• **जलवायु सहयोग: ऊर्जा भंडारण, ग्रिड रूपांतरण और अपतटीय पवन** पर सहयोग।
	• **व्यापारिक विस्तार:** द्विपक्षीय व्यापार को **2030 तक** दोगुना कर **120 बिलियन अमेरिकी डॉलर** करना।
	• **टैरिफ हटाना:**
	  ▸ **भारत:** वस्त्र, खिलौने, समुद्री उत्पाद तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं में लाभ।
	  ▸ **UK:** व्हिस्की, सैल्मन, चॉकलेट और एडवांसड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रकों के लिए लाभ।
	• **सीमा शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं को सरल करना:** व्यापार के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण।

निष्कर्ष

भारत-यूनाइटेड किंगडम CETA और विजन 2035 एक परिवर्तनकारी और वैश्विक नवाचार केंद्रों के रूप में निष्पक्ष, महत्वाकांक्षी और आधुनिक व्यापार समझौतों के लिए एक नया मानदंड स्थापित करता है।

4.9.2. भारत-यूरोपीय संघ संबंध {India-European Union (EU) Relations}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त** और **भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए **6 बिंदुओं** को रेखांकित किया गया ।

भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंधों का महत्व		
पारस्परिक संबंध	**भारत के लिए लाभ**	**प्रमुख चुनौतियां**
❖ 1962 के ऐतिहासिक संबंध; 2004 से दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी। ❖ **यूरोपीय संघ (EU)** भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है; **भारत** यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ❖ संयुक्त पहलें: **स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी** (2016) लॉन्च हुई, आदि।	❖ EU से भारत में **107.27 बिलियन डॉलर** का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। (2000 से 2023 के बीच) ❖ **निर्यात** को बढ़ावा (IT, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और कृषि क्षेत्रक) ❖ रणनीतिक मूल्य: उदाहरण के लिए, **एयरबस C-295 विमानों का विनिर्माण**। ❖ **इनोवेशन:** व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (2022)	❖ **गैर-शुल्क बाधाओं** के कारण **व्यापार में विविधता की कमी**। ❖ **FTA वार्ताओं में देरी:** डिजिटल क्षेत्रक पर नियम, CBAM, श्रम कानूनों, मानवाधिकारों जैसे विषयों पर मतभेद है। ❖ **चीन के आयात पर यूरोपीय संघ की निर्भरता:** भारत के सहयोग की तात्कालिकता को सीमित करता है

निष्कर्ष

भारत और यूरोपीय संघ, दोनों ही 'विविधता के संघ' हैं तथा लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों जैसे साझा मूल्यों में विश्वास रखते हैं। दोनों नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और प्रभावी बहुपक्षवाद को बनाए रखने के लिए साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।

4.9.3. भारत-फ्रांस संबंध (India-France Relations)

भारत-फ्रांस संबंधों के बीच बढ़ती घनिष्ठता	संबंधों में चुनौतियां
❖ **रक्षा सहयोग:** भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। (कुल आपूर्ति का 33%, SIPRI) ❖ **हिंद-प्रशांत रणनीति:** 2023 में समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए रोडमैप जारी किया गया। ❖ **अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी:** मिशन: तृष्णा/ TRISHNA, AI रोडमैप, सिस्टर इनोवेशन हब।	❖ द्विपक्षीय व्यापार के प्रदर्शन में कमी (2022 में 15.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार) ❖ पत्रकार एवं संवाददाताओं पर वीज़ा प्रतिबंध। ❖ वित्तीय और दायित्व संबंधी मुद्दे विद्यमान होने के कारण **जैतापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर प्लांट** स्थगित है। ❖ सामरिक स्वायत्तता को लेकर अलग-अलग मत, विशेषकर चीन के संदर्भ में।

आगे की राह

- **सामरिक स्वायत्तता में अंतराल:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस के संतुलनकारी कार्यों के साथ संरेखित करने के लिए लचीले दृष्टिकोण अपनाना।
- **सुरक्षा समन्वय को गहराना:** संयुक्त गश्त/ अभ्यासों, आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह का विस्तार करना।

निष्कर्ष

भारत-फ्रांस संबंध **"समुद्र से अंतरिक्ष तक"** और उससे आगे तक जाती है।" फ्रांस के राजदूत ने उल्लेख करते हुए कहा कि "भारत-फ्रांस साझेदारी **"सार्वभौमिक"** – जो वैश्विक नेतृत्व के उद्देश्य से इतिहास में निहित है।

4.9.4. भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने जुलाई 2024 में रूस की आधिकारिक यात्रा की, जहां उन्होंने **22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन** में भाग लिया और व्यापार व क्षेत्रीय सहयोग के लिए नए मानक स्थापित किए।।

भारत-रूस संबंधों का समकालीन महत्त्व	भारत-रूस संबंधों के समक्ष चुनौतियां
❖ **बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था:** एकतरफा कार्रवाई का विरोध करना; रूस द्वारा **UNSC** में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करना। ❖ **बहुपक्षीय सहयोग:** UN, ब्रिक्स और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करना।	❖ **भू-राजनीतिक संतुलन:** अमेरिका (क्वाड, प्रतिबंधों का जोखिम) और रूस दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करना। ❖ **रूस-चीन के बीच बढ़ते संबंध: 240 बिलियन डॉलर** से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार और पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाना। (उदाहरण के लिए, INSTC के लिए आमंत्रण)

❖ **रक्षा संबंध:** रूस भारत के रक्षा आयात का 36% **हिस्सा** आपूर्ति करता है; उदाहरण के लिए, **S400 एयर डिफेंस सिस्टम**, तुशील फ्रिगेट। ❖ **संयुक्त उत्पादन:** यह क्रेता-विक्रेता गतिशीलता से **आपसी विकास** में बदल गया है। (उदाहरण के लिए- ब्रह्मोस, AK203)	❖ **व्यापार असंतुलन:** 2023-24 में भारत ने रूस को 4.3 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जबकि रूस से 61.4 बिलियन डॉलर का आयात किया गया था। इसने रुपया-रूबल सौदे को भी जटिल बना दिया है। ❖ **सैन्य अंतर-संचालनीयता के स्तर में कमी:** सैन्य अभ्यास इंद्र का स्थगित होना; S-400 के बाद नए रक्षा समझौते। ❖ **सुदूर पूर्व कनेक्टिविटी की सीमाएं:** जापान, दक्षिण कोरिया के प्रतिबंधों से व्यापारिक गलियारा बाधित हो रहा है।

आगे की राह

- **व्यापार में विविधता लाना:** धातुकर्म, रासायनिक उद्योग और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रकों के उत्पादों को शामिल करना।
- **EAEU- भारत वार्ता:** मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाना।
- **रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS):** परस्पर सैन्य विनिमय और पहुंच को सरल बनाना।
- **क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को व्यापक बनाना:** किसी अन्य तीसरे देशों में संयुक्त परियोजना संचालित करना (उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर सहयोग)
- **टियर II कूटनीति:** युवा और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

प्रत्येक बदलाव एवं पुनर्संरेखण के माध्यम से, भारत और रूस ने पारस्परिक लाभ के लिए तथा क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता एवं समृद्धि में योगदान देने के लिए नए अवसरों को अपनाने और खोजने की असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है, जैसा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रेखांकित किया है।

4.9.5. भारत-यूरेशिया संबंध (India-Eurasia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने **पोलैंड, क्रोएशिया, साइप्रस, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और यूक्रेन** की यात्रा की, जो मध्य एवं पूर्वी यूरोप (CEE) के साथ राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

यूरेशिया तक भारत की पहुंच	द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति को बनाए रखना	यूरेशियाई परिदृश्य में चुनौतियां
❖ CEE देशों के साथ भारत की कूटनीतिक भागीदारी बढ़ी है। ❖ पोलैंड प्रमुख भागीदार के रूप में: CEE देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है। (2023 में द्विपक्षीय व्यापार 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) ❖ IMEEC गलियारा: एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को एकीकृत करना।	❖ रणनीतिक संबंध: रूस और आर्मेनिया के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करना। ❖ आर्थिक: भारत-यूरेशिया का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।	❖ संपर्क का अभाव: IMEC और INSTC की भौगोलिक और बुनियादी ढांचे में धीमी प्रगति। ❖ पाकिस्तान कारक: भौगोलिक सीमाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पहुंच यूरेशिया के लिए सीधे संपर्क को सीमित करती है ❖ BRI में प्रतिस्पर्धा: भारत की रणनीतिक विस्तारित पड़ोस पहल, जैसे कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को चुनौती देता है।

आगे की राह

- **कनेक्टिविटी को बढ़ाना:** ग्रेटर यूरेशिया कॉरिडोर और नॉर्थ-ईस्ट पैसेज से जुड़ना आवश्यक है।
- **यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत बनाना:** भारत की यूरेशिया नीति में यूरोपीय संघ के साथ बेहतर जुड़ाव को शामिल करना।

निष्कर्ष

"यूरेशिया भी भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है, जिसके साथ लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। जैसा कि श्याम सरन कहते हैं कि हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर पर भारत का समुद्री संपर्क और भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

4.9.6. भारत-नॉर्डिक संबंध (India-Nordic Relations)

संबंधों का अवलोकन	सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
❖ भारत-नॉर्डिक रणनीतिक संबंध **लोकतांत्रिक मूल्यों,** नवाचार तथा जलवायु कार्रवाई की मजबूत नींव पर आधारित हैं। ❖ नॉर्डिक देश: पांच देश- **डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड।** ❖ **व्यापार वृद्धि:** फिनलैंड और नॉर्वे को किए जाने वाले निर्यात में क्रमशः 100% और 80% से अधिक की वृद्धि। ❖ पांच नॉर्डिक देशों में से चार यूरोप में भारत के शीर्ष 20 व्यापारिक भागीदारों में से हैं।	❖ **ब्लू इकोनॉमी:** भारत-नॉर्वे एकीकृत महासागर प्रबंधन और अनुसंधान पहल। ❖ **भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन (2018, 2022):** भारत के साथ नॉर्डिक देशों का शिखर सम्मेलन स्तर पर विशेष सहयोग है।
संबंधों का महत्व	**संबंधों में चुनौतियां**
❖ **संधारणीयता संबंधी सहयोग:** नॉर्डिक भारतीय स्मार्ट सिटीज़ मिशन का समर्थन करता है। ❖ **नॉर्डिक नवाचार उत्कृष्टता:** भारत फिनलैंड द्वारा संचालित पांच वैश्विक नवाचार केंद्रों में से एक की मेजबानी करता है। जिन्हें फ़िननोड (FinNode) के रूप में जाना जाता है।	❖ **रूस- नाटो के गतिशील संबंध:** नॉर्डिक- नाटो (फिनलैंड, स्वीडन) संबंध बनाम भारत- रूस संबंध। ❖ **सदस्यों के अलग-अलग हित:** नीतिगत मुद्दों पर संयुक्त रूप से जटिल रुख अपनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ❖ **व्यापार बाधाएं:** टैरिफ व गैर-टैरिफ बाधाएं और जटिल विनियमन जैसे मुद्दे व्यापार एवं निवेश के अवसरों को सीमित करते हैं।

आगे की राह

- लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करना।
- जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के सहयोग में विकास।
- **प्रौद्योगिकी में साझेदारी:** खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ तकनीक के क्षेत्र में नॉर्डिक स्टार्टअप्स के साथ काम करना
- **लगातार कूटनीतिक संवाद:** नियमित उच्च-स्तरीय संवाद की सुविधा प्रदान करना।

निष्कर्ष

भारत-नॉर्डिक साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है, जिससे महत्वपूर्ण रणनीतिक अभिसरण हुआ है। यह द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था दोनों को समृद्ध करते है।

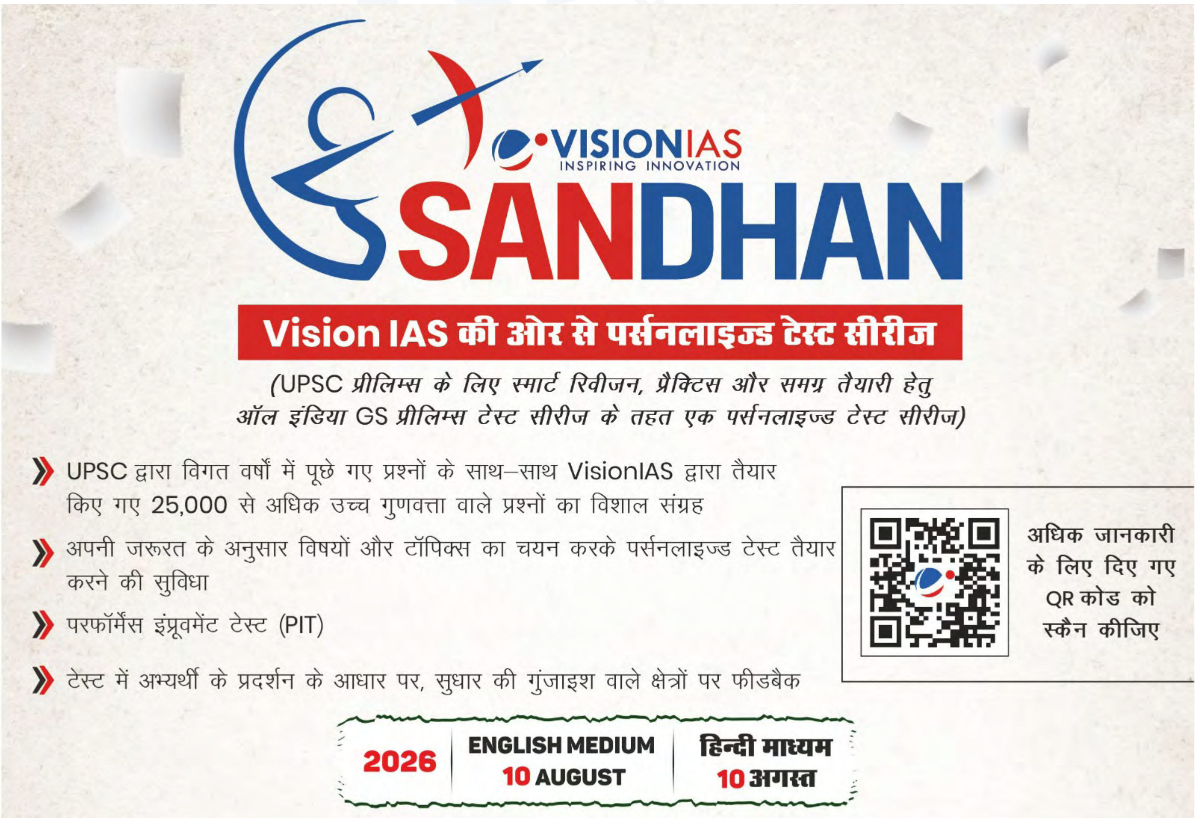

4.10. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India-Australia Relations)

द्विपक्षीय साझेदारी का महत्व	प्रमुख चुनौतियां
❖ रणनीतिक साझेदारी: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 2024 में भारत को 'शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार' के रूप में मान्यता दी है। ❖ रक्षा सहयोग: ऑस्ट्राहिन्द (AUSTRAHIND), ऑसिन्डेक्स (AUSINDEX), पिच ब्लैक जैसे सैन्य अभ्यासों का आयोजन; म्यूच्यूअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट और प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ❖ आर्थिक संबंध: ▸ ECTA (2021) ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है। ▸ ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य 2035 तक भारत को अपने शीर्ष तीन निर्यात बाजारों में शामिल करना। ▸ भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव के लिए एक नया रोडमैप जारी किया गया।	❖ व्यापार संबंधी मुद्दे: CECA वार्ता में देरी तथा गैर-व्यापारिक बाधाएं (NTBs), फार्मा मूल्य नियंत्रण। ❖ परमाणु अंतराल: परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए यूरेनियम व्यापार पर समझौता करना। ❖ खालिस्तानी समर्थकों में उग्रवाद: बढ़ती घटनाओं से विश्वास पर दबाव। ❖ वीजा शुल्क में लगभग 125% की वृद्धि से भारतीय छात्रों पर बोझ।

आगे की राह

- आर्थिक भागीदारी: CECA पर वार्ता पूरी करना, इसके अतिरिक्त ग्रीन ऊर्जा, खनन, प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।
- सुरक्षा पर फोकस: समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद-रोधी सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने की आवश्यकता है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना: आसियान, PIF के तहत छोटे द्वीपीय देशों से सहयोग बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित हैं। हमारे संबंध क्रिकेट, करी और राष्ट्रमंडल से कहीं आगे है। यह डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, दोस्ती और सबसे महत्वपूर्ण, आपसी विश्वास से परिभाषित होता है - जैसा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की है।

4.11. भारत और LAC (लैटिन अमेरिका और कैरिबियन) क्षेत्र संबंध {India and LAC (LATIN AMERICA and Caribbean) Region Relations}

भारत के लिए लैटिन अमेरिका का महत्त्व	भारत के लिए लैटिन अमेरिका में चुनौतियां
❖ व्यापार और पहुँच: LAC भारत के आयात स्रोतों में 8वें स्थान पर है। चिली के साथ CEPA पर हस्ताक्षर आदि। ❖ दक्षिण-दक्षिण सहयोग: भारत ने 29 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के साथ ग्लोबल साउथ सम्मेलन आयोजित किया था। ❖ रणनीतिक महत्व: तांबे के वैश्विक उत्पादन में लगभग 40% का योगदान करता है। साथ ही, विश्व के 35% लिथियम की आपूर्ति करता है। ❖ भू-राजनीतिक हित: UNSC, NSG में भारत द्वारा अपनी सदस्यता सुनिश्चित करने जैसी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण। ❖ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा: ब्राजील और लैटिन अमेरिका का उपजाऊ भूमि का क्षेत्र, इथेनॉल और खाद्य भंडारण प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण है।	❖ कूटनीतिक अभाव: उच्च स्तर पर पर्याप्त ध्यान न देना और पर्याप्त संस्थागत उपस्थिति का अभाव। ❖ टैरिफ संबंधी मुद्दे: लैटिन अमेरिकी देशों के कृषि उत्पादों पर भारत द्वारा चीन की तुलना में 5 गुना अधिक प्रशुल्क लगाना।

आगे की राह

- **व्यापार विविधीकरण:** 2027 तक दोतरफा व्यापार को 100 बिलियन डॉलर करना, PTAs को FTAs में अपग्रेड करना।
- **LAC के फोकस में सुधार करना:** LAC कार्यक्रम को पुनर्जीवित करना; व्यापार और सामरिक प्रौद्योगिकियों पर मंत्रिस्तरीय परिषद की स्थापना करना, आदि।

निष्कर्ष

लैटिन अमेरिका भारत को व्यवसाय के लिए **'गोल्डीलॉक्स ज़ोन'** का हिस्सा बनाता है, यह पश्चिम के अत्यधिक विनियमित एवं प्रतिस्पर्धी बाजार एवं अफ्रीका केकम प्रतिस्पर्धी एवं कम क्रय शक्ति वाले बाजार के बीच का संतुलित क्षेत्र है, जो कि भारत के वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनता है।

5. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच तथा उनकी संरचना व अधिदेश (IMPORTANT INTERNATIONAL INSTITUTIONS, AGENCIES, AND FORA, THEIR STRUCTURE, MANDATE)

5.1. अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (International Humanitarian Law: IHL)

महत्वपूर्ण सिद्धांत	प्रवर्तन में चुनौतियां	भारत की भूमिका
❖ विभेद: नागरिकों और नागरिक संपत्ति पर प्रत्यक्ष हमले को प्रतिबंधित करता है। ❖ आनुपातिकता: आकस्मिक नुकसान का पूर्वानुमान लगाना और उसे न्यूनतम करना। ❖ पूर्वोपाय: नागरिक आबादी की रक्षा करने हेतु सतत देखभाल करने की जिम्मेदारी।	❖ राज्य गैर-अनुपालन: IHL की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना (उदाहरणार्थ, सीरिया, म्यांमार) ❖ गैर - राज्य कर्ता: सशस्त्र समूह अक्सर IHL को मान्यता नहीं देते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं। ❖ संस्थागत बाधाएं: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति (सीरिया मामले में रूस/ चीन की वीटो शक्ति)।	❖ संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ❖ सैन्य प्रशिक्षण: भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में IHL को शामिल किया जाता है। ❖ शांति स्थापना नेतृत्व: संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष 3 सैन्य योगदानकर्ता

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार: वीटो शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता, और अधिक प्रतिनिधिक बनाना।
- घरेलू कानूनी एकीकरण: राष्ट्रीय कानूनों में IHL को शामिल करना।
- तकनीकी शासन: स्वचालित हथियार प्रणालियों और साइबर युद्ध के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों को विनियमित करना।

निष्कर्ष:

अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) आज गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वीटो-आधारित राजनीति हो या स्वचालित हथियारों की बढ़ती मौजूदगी। ऐसे परिदृश्य में भारत को एक अग्रणी शांतिरक्षक राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका का लाभ उठाते हुए, राज्यों और गैर-राज्य पक्षों के बीच प्रवर्तन की खाई को पाटने की दिशा में सक्रिय और रचनात्मक पहल करनी चाहिए।

5.2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आधारभूत भूमिका	कार्यात्मक प्रासंगिकता
❖ UNSC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में की गई थी। ❖ परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।	❖ **शांतिपूर्ण विवाद समाधान** : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्राथमिक अधिदेश ❖ **प्रतिबंध लगाना एवं शांति मिशन:** यह 3 महाद्वीपों में 11 ऑपरेशन की देखरेख करता है।
UNSC में सुधारों की आवश्यकता क्यों?	**सुधारों में चुनौतियां**
❖ **प्रतिनिधित्व का अभाव:** अस्थायी सदस्यों में **अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन का** कोई प्रतिनिधित्व नहीं है; एशिया-प्रशांत का प्रतिनिधित्व कम है। ❖ **विश्वसनीयता में गिरावट:** संघर्षों को सुलझाने में विफलता, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध।	❖ **चार्टर में संशोधन:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता है। ❖ **समूहों का विरोध: G4/L.69 समूह (विकासशील राष्ट्र)** के प्रस्तावों **को कॉफ़ी क्लब** से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। **(इटली, पाकिस्तान, आदि)**

निष्कर्ष:

बढ़ती बहुध्रुवीयता के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। भारत का यह प्रयास वैश्विक शासन को लोकतांत्रिक बनाने की बढ़ती माँग को दर्शाता है।

5.3. भारत और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (India and UN Peacekeeping)

भारत का वैश्विक योगदान	भारत के लिए रणनीतिक लाभ
❖ सैन्य तैनाती: 1950 के दशक से अब तक शांति स्थापना मिशनों में 2,87,000 के आस-पास सैनिकों की सेवाएं प्रदान की हैं। ❖ प्रशिक्षण केंद्र: 12,000 से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK) की स्थापना की गई है।	❖ कूटनीतिक लाभ: UNSC की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मजबूत करना। ❖ सुरक्षा फुटप्रिंट: संघर्ष क्षेत्रों में ऊर्जा/ आर्थिक हितों की रक्षा करना।
प्रणालीगत चुनौतियाँ	**भारत का सुधार एजेंडा**
❖ शक्ति असंतुलन: निर्णय लेने की प्रक्रिया में सैनिकों और पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती। ❖ अनावश्यक मिशन: UNMOGIP (भारत-पाकिस्तान) की प्रासंगिकता का अभाव।	❖ विवेकपूर्ण तैनाती: शुरू से ही क्लियर एग्जिट रणनीति" को ध्यान में रखना, यथार्थवादी जनादेश ❖ क्षेत्रीय साझेदारियां: संघर्ष मध्यस्थता में AU, आसियान को सशक्त बनाना

निष्कर्ष:
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में शीर्ष योगदानकर्ता होने के नाते, भारत संचालन संबंधी उत्कृष्टता को संरचनात्मक सुधार की पहल से जोड़ता है, जिससे एक अधिक सक्षम और प्रभावी वैश्विक संघर्ष-निवारण तंत्र का निर्माण संभव होता है।

5.4. ICC

गंभीर अपराधों से निपटने में ICC की भूमिका	चुनौतियां
❖ **गंभीर अपराध हेतु मुकदमा चलाना:** जब घरेलू न्यायालय अत्याचारों का अभियोजन करने में विफल रहते हैं तब यह नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के मामलों में अंतिम उपाय के रूप में कार्य करता है। ❖ **पीड़ित-केंद्रित अप्रोच:** पीड़ितों के लिए ट्रस्ट फंड (TFV) से 2023 में 26,000 से अधिक लाभार्थियों की सहायता की गई। ❖ **वैश्विक शासन:** सदस्य देशों की सभा लोकतांत्रिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करती है।	❖ **प्रवर्तन का अभाव:** सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर (उदाहरण के लिए, सूडान के राष्ट्रपति अल-बशीर की गिरफ्तारी का मामला)। ❖ **राजनीतिक पक्षपात:** 54 में से 47 अभियुक्त अफ्रीकी हैं, जिससे उपनिवेशवाद के आरोपों को बल मिलता है।

आगे की राह
- **गिरफ्तारी तंत्र को मजबूत करना:** इंटरपोल सहयोग , गैर-अनुपालन के लिए प्रतिबंध
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार संबंधी संदर्भ:** अत्याचार के मामलों में UNSC के वीटो पॉवर को सीमित करना
- **अभियोजन में विविधता लाना:** कथित अफ्रीकी-विरोधी पूर्वाग्रह को दूर करना

निष्कर्ष:
"अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का भविष्य उसी समय साकार हो सकता है जब सार्वभौमिक न्याय के आदर्श को व्यवहार में उतारा जाए।" कोफी अन्नान के इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक है कि भूराजनीतिक हस्तक्षेप और प्रवर्तन की कमजोरियों को दूर किया जाए, ताकि विश्व के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और न्याय प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर सके।

5.5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO)

अधिदेश और कार्य

- 1946 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के दौरान WHO के संविधान को अपनाया गया। बाद में यह 1948 में लागू हुआ।
- WHO **स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करता है,** लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, एवं स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सेवाओं का विस्तार करता है।

प्रमुख योगदान	वैश्विक पहलें
❖ UHC (उदाहरण के लिए- WHO की ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी), पोलियो के उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयास। ❖ स्वास्थ्य आपात स्थितियों की घोषणा करना (PHEIC) ❖ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानूनों को विनियमित करना।	❖ आपातकालीन प्रतिक्रिया फ्रेमवर्क्स। ❖ स्वास्थ्य कार्य योजनाएँ (जैसे, टीबी, पोलियो उन्मूलन, पोषण) ❖ कल्याण एवं बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा (जैसे, आत्महत्या की रोकथाम, हेल्दी एजिंग) ❖ वैक्सीन प्रौद्योगिकी और वैश्विक जीनोमिक निगरानी पहल, नवाचार।
कमियां	**सुधार**
❖ राजनीतिक दबाव (विशेष रूप से चीन, अमेरिका का) ❖ अपर्याप्त समन्वय और विभागों के कार्यों में ओवरलैपिंग। ❖ खराब वित्तपोषण, फार्मास्यूटिकल क्षेत्रक का प्रभाव और प्रभावी कानूनी शक्तियों का अभाव।	❖ स्वास्थ्य सुधारों में नेतृत्व का समर्थन करने के लिए 2017 का एजेंडा। ❖ 2024 में सतत वित्तपोषण हेतु निवेश दौर। ❖ आउटपुट-आधारित प्रगति को ट्रैक करना। ❖ गूगल एवं फीफा जैसे संगठनों के साथ साझेदारी।

निष्कर्ष:

WHO भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार संगठन है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) और रोग नियंत्रण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, हालांकि इसे निरंतर सुधारों की आवश्यकता है।

5.6. राष्ट्रमंडल (Commonwealth)

राष्ट्रमंडल में भारत की भूमिका	भारत के लिए रणनीतिक लाभ	चुनौतियां
❖ **नेतृत्वकर्ता:** राष्ट्रमंडल की कुल आबादी में से लगभग 60 प्रतिशत आबादी के साथ राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश। ❖ **कार्यक्रम की मेज़बानी** : 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर (CHOGM) सम्मेलन और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी।	❖ **सॉफ्ट पावर को बढ़ावा:** अफ्रीका, कैरिबियन और प्रशांत देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना। ❖ **व्यापार लाभ:** व्यापारिक भागीदारों के लिए द्विपक्षीय लागत औसतन 21 प्रतिशत कम है।	❖ **औपनिवेशिक विरासत:** उपनिवेशवाद को वैधता प्रदान करने का आरोप ❖ **संकट की स्थिति में सीमित कार्रवाई:** कोविड-19 महामारी के दौरान कमजोर समन्वय ❖ **वित्तीय निर्भरता:** यूनाइटेड किंगडम की वित्तीय सहायता पर अत्यधिक निर्भरता

निष्कर्ष:

राष्ट्रमंडल भारत को समावेशी कूटनीति, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सतत विकास संबंधी नेतृत्व के लिए एक मंच प्रदान करता है।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

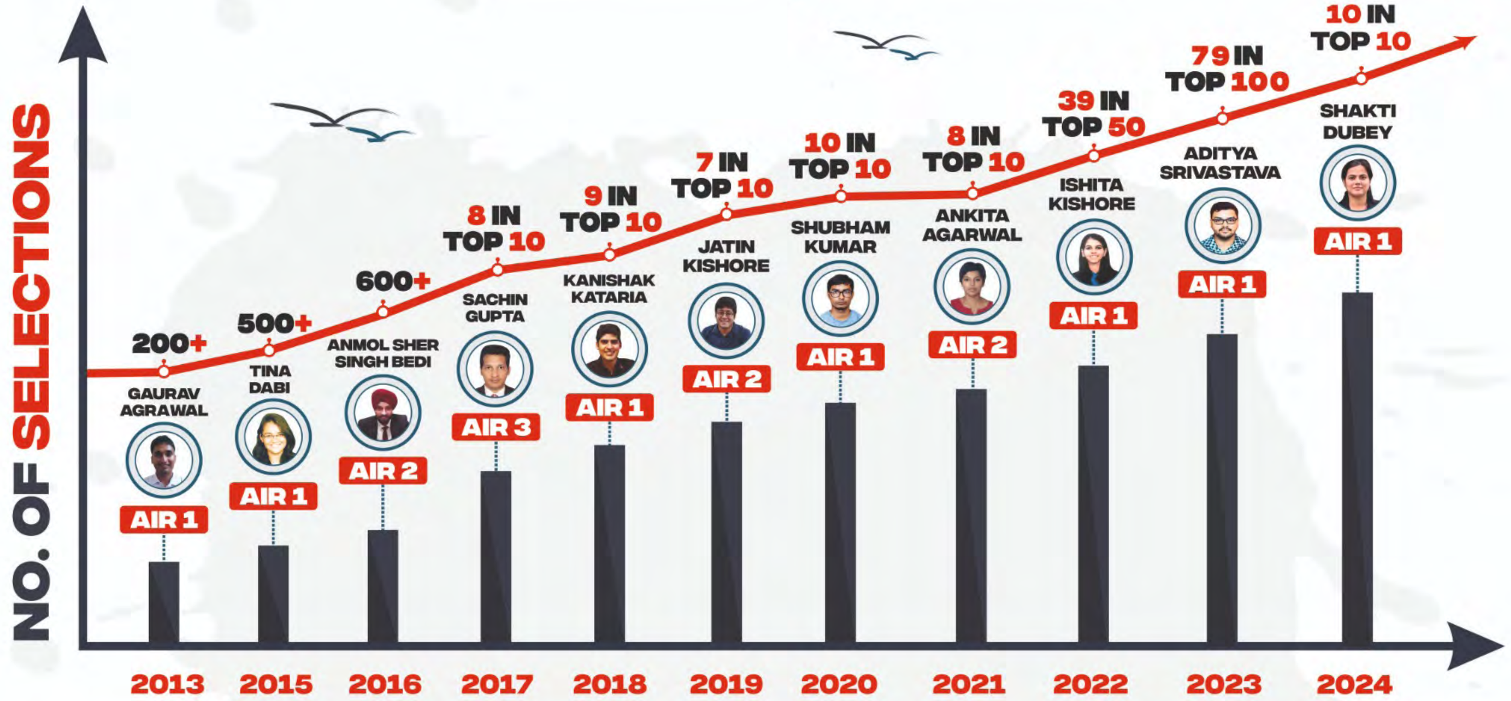

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course

GENERAL STUDIES

PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 7 AUGUST, 11 AM | 14 AUGUST, 8 AM | 19 AUGUST, 5 PM
22 AUGUST, 11 AM | 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM

हिन्दी माध्यम 7 अगस्त, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 25 AUG | BHOPAL: 18 AUG | CHANDIGARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 11 AUG | JAIPUR: 5 & 10 AUG | JODHPUR: 10 AUG | LUCKNOW: 22 JULY | PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 10 अगस्त

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Shakti Dubey

2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom **Student**

3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom **Student**

4 AIR
Shah Margi Chirag

5 AIR
Aakash Garg

6 AIR
Komal Punia

7 AIR
Aayushi Bansal

8 AIR
Raj Krishna Jha

9 AIR
Aditya Vikram Agarwal

10 AIR
Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR
Ankita Kanti

182 AIR
Ravi Raaz

438 AIR
Mamata

448 AIR
Sukh Ram

509 AIR
Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE (DELHI)
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची